● वर्ष-3
● अंक-193
रायपुर, गुरुवार
21 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› जानिए वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के...

सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास भाजपा की नीतिः मुख्यमंत्री

भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक बन सकता हैः साय

दंतेवाड़ा/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि लोकसभा 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत मां दंतेश्वरी के आँचल दंतेवाड़ा से करने का अवसर मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ख्याति आज विश्व भर में है। सारा विश्व उन्हें आज अपना नेता माना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हमें विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त है। आज मोदीजी के नेतृत्व में देश का जैसा चारों तरफ विकास हुआ है, जिस तरह मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सभी सपनों को साकार किया है, पार्टी के मनीषियों द्वारा लिए गए हर संकल्प की सिद्धि की है, वह अपने आपमें गौरव का भाव हममें भरता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अयोध्या जी में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनना, रामलला की अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा, जम्मू-कश्मीर से 370 समाप्त होना समेत पार्टी ने उन सभी कार्यों को पूरा कर लिया है, जिसके नारे लगाते हुए हम सभी आज यहां तक पहुँचे हैं। हमारे पास आज भाजपा कार्यकर्ता के रूप में गर्व करने के सैकड़ों कारण हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर ही आप सभी ने छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से और ऐतिहासिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायी है। हम सबके लिए यह संतोष का विषय है कि हमने मात्र तीन महीने के कार्यकाल में लगभग सभी बड़ी गारंटियों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि की गारंटियां दी थीं, आप लोगों ने उनकी गारंटी पर भरोसा किया था। आपने यह भी देखा है कि हमने केवल तीन महीनों के भीतर उनमें से अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी ने माताओं और बहनों को गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बनने पर उन्हें हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। इस गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश में महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि 655 करोड़ रुपए पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी जी ने किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस देने की गारंटी दी थी। सुशासन दिवस पर राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस वितरित कर दिया गया। गारंटी के अनुरूप इस साल हम लोगों ने 3100 रुपए क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। इस साल प्रदेश में 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को धान खरीदी के समर्थन मूल्य की राशि 32 हजार करोड़ रुपए का भुगतान तत्काल कर दिया गया। इसके बाद कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की अंतर की राशि का भुगतान भी कर दिया गया। इससे राज्य के 24 लाख 75 हजार किसानों को लाभ हुआ है। कुल करीब 45 हजार करोड़ रूपये किसानों के खाते में गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को 4000 रुपय मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपया मानक बोरा कर देगी। इसकी घोषणा भी कोंडागांव में कर दी है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी से 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

उप्र में 2014 से ज्यादा, बंगाल में 25 सीटें, बिहार में बड़े भाई की भूमिकाः शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दावा किया कि इस बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उत्तर प्रदेश में 2014 से अधिक सीट मिलेंगी और जनता सभी वंशवादी दलों को सबक सिखाएगी. शाह ने दो टूक कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भाजपा के एजेंडे में शामिल है क्योंकि पार्टी का मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सभी लोगों के लिए एक समाना कानून होने चाहिए. एक समिट में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में हमें इस बार 2014 की तुलना में अधिक सीट मिलेंगी. भाजपा को 2014 में उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीट में से 71 सीट पर जीत मिली थी जबकि उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में दो सीट गई थीं. पार्टी को 2019 के चुनाव में प्रदेश की 62 सीट मिलीं और उसके सहयोगी दल को दो सीटें मिलीं. ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के साथ भाजपा के गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर अंतिम निर्णय लेंगे. शाह ने कहा, हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है. हमारी पार्टी के अध्यक्ष फैसला करेंगे. लेकिन यह निश्चित है कि हम ओडिशा में भारी जीत हासिल करेंगे. उन्होंने कहा, ''अगर हम अकेले लड़ने का फैसला करते हैं तो हम ओडिशा में सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे. ओडिशा में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे. पंजाब में गठबंधन की बातचीत जारी है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह अगले दो से तीन दिनों में स्पष्ट हो जाएगा. शाह ने कहा, बातचीत जारी है. हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी दल एक साथ आएं. बिहार के बारे में शाह ने कहा कि यह पहली बार है, जब भाजपा अपने सहयोगियों से अधिक सीटों के साथ लोकसभा चुनाव बड़े भाई के रूप में लड़ने जा रही है. बिहार में राजग के बीच हुए सीट-बंटवारे के मुताबिक भाजपा कुल 40 में से 17 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) 16 सीट पर, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पांच सीट पर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे. शाह ने दावा किया कि भाजपा को पश्चिम बंगाल की कुल 42 में से 25 से अधिक सीटें मिलेंगी. उन्होंने कहा कि पार्टी को दक्षिणी राज्यों, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में भी अधिक संख्या में सीट मिलेंगी.

चुनाव समय पर ही होंगे- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही सितंबर के अंत तक की समय सीमा तय कर दी है और चुनाव उससे पहले होंगे.

चुनावी बॉण्ड से भाजपा को मुख्य रूप से लाभ होने के दावे को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि इसके खत्म होने के बाद चुनावी वित्तपोषण में काले धन की वापसी की संभावना है. उन्होंने कहा, ''ऐसा आरोप है कि हमें बहुत अधिक चंदा मिला है. यह पूरी तरह से झूठ है. हमें 6,200 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले ' इंडिया% गठबंधन को 6,200 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं. हमारे पास लोकसभा में 303 सीट है.

यूसीसी 1950 से हमारा मुद्दा है

यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि यह लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है जिसे पार्टी छोड़ नहीं सकती. उन्होंने कहा, यूसीसी 1950 से हमारा मुद्दा है. हमारी पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया है. हम इससे दूर नहीं जा सकते. हमारा मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए. यूसीसी देश की जनता से भाजपा का वादा है. भाजपा शासित उत्तराखंड ने पिछले महीने यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक कानून बनाया, ताकि अलग-अलग आस्था के बावजूद सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम सुनिश्चित किए जा सकें. अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह के कानून लाए जाने की उम्मीद है.

सीएएः मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं हैः अमित

शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के बारे में कथित तौर पर भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की. केंद्र ने हाल में सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियम जारी किए हैं. उन्होंने कहा, वोट बैंक के लिए विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि सीएए देश के अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन लेगा. लेकिन सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा, केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, '' इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है. सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है.

राहुल के शक्ति वाले बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा

नई दिल्ली। राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाली टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणियों को शब्दशः पढ़ा और चुनाव आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी। राहुल गांधी ने रविवार को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था, ''हिन्दू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं...एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है...सही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है... हिंदुस्तान की हर संस्था में है। ईडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में है।''

चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पुरी ने कहा, उन्होंने जो कहा, मैंने वही पढ़ा और फिर हमने जाकर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। पुरी ने बताया कि उन्होंने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर भाजपा के हमले का नेतृत्व करते हुए कहा कि जो लोग शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं, सरकार ने सुको में दिया हलफनामा

नई दिल्ली। सरकार ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा अधिनियम के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए हानिकारक होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि असमर्थित और हानिकारक बयानों के आधार पर राजनीतिक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को खारिज कर दिया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को शीर्ष अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश को रोकने के लिए 14 मार्च को जल्दबाजी में नियुक्त किया गया था।

प्रमुख समाचार

पुतिन-जेलेंस्की ने चुनाव के बाद मोदी को किया आमंत्रित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की. दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जारी युद्द के बीच हुई है. सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने कहा कि वे भारत को शांतिदूत के रूप में देखते हैं. सूत्रों ने कहा कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2018 में रूस का दौरा किया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की और उन्हें शांति के सभी प्रयासों और रूस-यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के लगातार समर्थन से अवगत कराया. प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की से यह भी कहा कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा. इस बीच, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को भारत की निरंतर मानवीय सहायता की सराहना की.

अपना दल ने यूपी की इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान

लखनऊ। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की सदस्य अपना दल (कमेरावादी) आगामी लोकसभा चुनाव यूपी की तीन सीटों फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशांबी से लड़ेगी। अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि आज गठबंधन के तहत हम अपनी तीन सीटें फूलपुर, मिर्ज़ापुर, कौशांबी घोषित कर रहे हैं। इन तीन सीटों तक हमारी बातचीत इंडिया गठबंधन से हुई थी और हम लगातार इंडिया गठबंधन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन तीन सीटों के लिए हम लगातार इंडिया गठबंधन से बात कर रहे हैं। पल्लवी पटेल इन्हीं में से किसी सीट पर चुनाव लड़ेंगी। कृष्णा पटेल ने यह भी कहा कि हम विधानसभा चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल की मां हैं, जो सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, जहां उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर जीत हासिल की थी।

दानिश अली कांग्रेस में शामिल अमरोहा से लड़ सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से निलंबित लोकसभा सांसद दानिश अली बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। यह बात अली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में 10 जनपथ स्थित उनके आवास पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने और उनका आशीर्वाद मांगने के पांच दिन बाद आई है। रिपोर्टों के मुताबिक, सबसे पुरानी पार्टी अली को उत्तर प्रदेश में अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है, यह सीट कांग्रेस ने अपनी सीट-बंटवारे की बातचीत में समाजवादी पार्टी से हासिल की थी। 14 मार्च को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद, अली ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस में शामिल होने के बारे में एक बड़ा संकेत दिया। इसके बाद उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि मेरे दूसरे लोकसभा चुनाव में अमरोहा से चुनाव लड़ने के लिए त्याग की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनका दिल भारत के गरीबों के लिए धड़कता है.

केजरीवाल को ईडी की जांच में सहयोग देना ही होगाः सचदेवा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आज हाई कोर्ट में ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन को चुनौती देने के मामले की सुनवाई के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब समय आ गया है की केजरीवाल बहाने बाजी छोड़ कर ई.डी. एवं अन्य जांच ऐजेंसियों से सहयोग करें। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की केजरीवाल की खुद की अर्जी पर हाई कोर्ट की प्रारम्भिक सुनवाई से स्पष्ट है कि सभी ई.डी. सम्मन वैध थे और केजरीवाल को व्यक्तिगत थे, उनकी पार्टी से सम्मन का कोई लेना देना नही है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ना प्रोटेक्शन दी, ना कल 21 मार्च के ई.डी. सम्मन पर रोक लगाई है, अब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को जांच में सहयोग देना चाहिए और जिस प्रकार से ईडी द्वारा सम्मन भेजे जाने का कुप्रचार आम आदमी पार्टी के नेता करते रहे हैं उन सभी की आवाज आज कोर्ट के निर्देशों ने बंद कर दी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है।

अजित पवार को परिवार से कर दिया गया अलग-थलग?

मुंबई। पहली बार पवार परिवार का अंदरूनी विवाद सामने आया है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी भाई श्रीनिवास पवार ने बारामती के काटेवाड़ी के ग्रामीणों के सामने अपना पक्ष रखा। इस बार उन्होंने अजित पवार की आलोचना की है। इसके बाद अजित पवार गुट ने भी जवाब दिया है। अजितदादा गुट ने आरोप लगाया है कि अजित पवार को पवार परिवार में अलग-थलग कर दिया गया है। इसका जवाब अब विधायक रोहित पवार ने दिया है। रोहित पवार ने आज जलगांव जिले का दौरा किया। उस वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई विषयों पर टिप्पणी की थी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर अलग-थलग पड़ने का आरोप लगा है। श्रीनिवास पवार ने अजित दादा की भी आलोचना की। इस पर विधायक रोहित पवार ने टिप्पणी की। श्रीनिवास पवार ने दिखा दिया कि शरद पवार को छोड़ना ठीक नहीं है। विधायक रोहित पवार ने प्रतिक्रिया दी है कि महाराष्ट्र में आम लोगों की भी यही राय है। रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार को पवार परिवार ने अलग-थलग नहीं किया है बल्कि अजित पवार खुद ही अलग-थलग पड़ गए हैं।

सरकार बनाने में महिला मतदाताओं की होगी अहम भूमिका

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 18 वीं लोकसभा के चुनाव का विगुल बज गया है। मुख्य चुनव आयुक्त राजीव कुमार ने 18 वीं लोकसभा के लिए सात चरणों में मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया हैं वहीं 4 जून को मतगणना की तारीख तय की गई है। सीधी सी बात है कि 4 जून को दोपहर बाद तक 18 वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर यह सब अलग बात है पर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। गत दो चुनावों ने देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि 2019 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीद्वारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2019 के आमचुनाव में 78 महिला सांसद चुन कर आई। हांलाकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते है।

खैर सबसे अच्छी बात यह है कि गॉव हो या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही है। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीद्वारी भी जताती है तो चुनाव केंपेन के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती है। दूसरी और मतदान में आगे आकर हिस्सा लेने लगी है। पिछले चुनावों के आंकड़ों से यह सब साफ हो चुका है। इस साल देश में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता है तो इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख के करीब है। एक मोटे अनुमान के अनुसार पुरुषों की तुलना में करीब दो करोड़ महिला मतदाता कम है। कमोबेस यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान थी। इस सबके बावजूद पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं के मतदान का आंकड़ा अधिक है।

2019 के चुनावों में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 67.02 प्रतिशत रहा तो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 67.18 प्रतिशत रहा। पूर्वोत्तर, हिमाचल, गोवा, बिहार सहित बहुत से प्रदेशों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। यह तो रही मतदान की बात तो दूसरी और नई सरकार बनाने में भी महिला मतदाताओं की अधिक भूमिका रही है। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया या यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार बनने और 2019 में रीपिट होने का प्रमुख कारण भी महिलाओं को भाजपा और खासतौर से नरेन्द्र मोदी पर अधिक भरोसा जताने को जाता है। 2004 के चुनावों में 22 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा और 26 प्रतिशत पुरुषों ने कांग्रेस को वोट दिया था वहीं 2019 के चुनाव आते आते इसमें जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। 2019 के चुनावों में महिलाओं द्वारा मोदी में विश्वास व्यक्त करने का आंकड़ा 36 प्रतिशत पहुंच गया। यानी कि 2019 के चुनावों में 36 फीसदी महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। महिलाओं के अधिक मतदान का ही परिणाम रहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और नरेन्द्र मोदी को जबरदस्त मेजोरिटी प्राप्त हुई।

विगत दो लोकसभा चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल घोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास होंगे। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और उसको दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम विगत चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। खास तौर से आने वाले दिनों में चुनाव केंपेन महिला केंद्रीत हो तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। देश की विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनावों में हम यह साफ रुप से देख चुके हैं।

बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई चिंता, खेतों में बिछी गेहूं की फसल

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में तीन दिनों के लगातार बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज फिर सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। जहां इलाके में घना कोहरा छाया रहा। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इससे गेहूं की फसल का काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं, मौसमी फल आम-अमरूद को भी नुकसान हुआ है। सब्जियों पर भी इसका असर देखने को मिला है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तीन दिन की लगातार झमाझम बारिश एवं ओलावृष्टि के बाद क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की खाड़ी फैसले एवं गर्मी का धान बोने वाले लोगों की किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं जबकि आम को भी ओलावृष्टि की मार झेलनी पड़ी है। पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई उससे किसानों की खड़ी फसल जिसमें डोरी, चार चिरोंजी, चना, गेहूं, महुआ, आम, के साथ सब्जियों की खेती करने वालो किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनकी खड़ी फसल ओलावृष्टि के चलते बर्बाद हो गई हैं।

कल शाम मध्यप्रदेश के अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के गौरेला के ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के साथ तरईगांव इलाके में ओलावृष्टि हुई। जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र पर ओलावृष्टि के बाद अमरकंटक से वापस आ रहे श्रद्धालू सड़क पर मस्ती करते नजर आए।

तेज आंधी तूफान से घर की छत टूटी सोते समय हुए हादसे में कई घायल

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम देवरी में अंधी तूफान और बारिश से किसान के मकान की छत उड़ गई। वहीं छत का कुछ हिस्सा मकान के अंदर सो रहे लोगों पर भी गिरा जिसमे मामूली चोट आई है। घर के अंदर रखे लगभाग पांच लाख रुपये के सामानों का नुकसान हुआ है। किसान ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को लेकर पटवारी को आवेदन दिया है, वही कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है।

मिली जानकारी अनुसार, जांजगीर चांपा जिले में दो दिनो से मौसम खराब होने से तेज आंधी तूफान और मुसलाधार बारिश हो रही है। जिससे लोगों का जीवन अस्त- व्यस्त हो गया है। वहीं अकलतरा तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरी में किसान सहदेव धिरही के घर का छत आई तेज आंधी तूफान के कारण सिमेंट की छत उड़ गई। और उसका कुछ हिस्सा मकान के अंदर जा गिरा जिससे मकान में सो रहे लोगों की हल्की फुल्की चोट आई है।

घटना की जानकारी गांव के सरपंच को दी गई और पटवारी को भी आवेदन दिया गया। जहां पटवारी ने मौके पर पहुंच कर नुकसान की जानकारी ली और प्रतिवेदन तैयार किया गया है। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की गई।

हसदेव अरण्य के 17 गांवों को मिला सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार

कोरबा। तकरीबन 2 दशक के संघर्ष के बाद कोरबा के अंतिम छोर पर मौजूद हसदेव अरण्य क्षेत्र के 17 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार मिल गया है। इन सभी गांव की ग्राम सभाओं ने वन अधिकार मान्यता कानून साल 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन के दावों को विधिवत प्रक्रिया के तहत उपखंड स्तरीय समिति में जमा किया था। हालांकि जिन क्षेत्रों के लिए यह दावा किया गया था, उन क्षेत्रों में कोल ब्लॉक प्रस्तावित होने के कारण वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब जाकर लंबे समय बाद ग्रामीणों को जल, जंगल और जमीन पर हक मिला है। कोरबा के सरहदी क्षेत्र के गांव मदनपुर, धजाक, खिरटी, मोरगा, दिधमुड़ी सहित 17 गांवों को यह अधिकार मिला है।

साल 2021 में राज्य सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र के 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया था, जिससे इस क्षेत्र में प्रस्तावित कोल ब्लॉक की स्वीकृति की प्रक्रिया रोकते हुए आबंटन रद्द किए गए थे। इसी समय हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति ने रायपुर तक पदयात्रा भी की थी। लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने के बाद जिला स्तरीय समिति ने सभी दावों को स्वीकृत कर सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षो में 4 हजार से अधिक गांव में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार मान्य किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उन सभी गांव में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति यानी कि सीएफएमसी का गठन किया गया है। इसका गांव स्तर पर गठन कर जंगल की सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

वहीं, अधिकार मिलने का बाद सामुदायिक वन संसाधन प्राप्त गांव की ग्रामसभा अपने वन संसाधनों की प्रबंधन योजना तैयार कर वन विभाग के सहयोग से जंगल का संरक्षण, प्रबंधन और पुनरूत्पादन का कार्य करेंगे। राज्य सरकार ने प्रत्येक सीएफएमसी के लिए बजट भी जारी किया है।

संयोजक सदस्य आलोक शुक्ला ने कहा यह एक सुखद अवसर है, जिस जंगल में खनन परियोजना प्रस्तावित थी। अब ग्रामसभा उस जंगल का संरक्षण और प्रबंधन करेगी। वनाधिकार मान्यता कानून आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए बनाया गया था। इस कानून का जितना प्रभावी क्रियान्वयन होगा आदिवासी और अन्य वन पर निर्भर समुदाय के साथ यह उतना ही न्याय होगा। हसदेव के सरगुजा क्षेत्र में वनाधिकार मान्यता कानून का उल्लंघन करके खनन के लिए जंगल की कटाई के कार्यों को भी रोका जाना चाहिए।

हसदेव अरण्य बचाओ समिति के संयोजक उमेश्वर सिंह आर्मो और पंचायतों के सरपंचों ने इसे संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत करार दिया है। साथ ही हसदेव अरण्य के समृद्ध जंगलों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

रामलला दर्शन योजना के खिलाफ याचिका खारिज

■ बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका नहीं माना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामलला दर्शन योजना के खिलाफ लगी जनहित याचिका खारिज कर दिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया और इस याचिका को जनहित याचिका नहीं माना। इसलिए इसे चलने लायक नहीं कहते हुए याचिका खारिज कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता लखन सुबोध ने जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में श्री रामलला दर्शन योजना को बंद करने की मांग की गई थी। साथ ही बताया गया कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के खिलाफ राज्य सरकार यह योजना चला रही है। याचिका में सरकार के धार्मिक यात्रा कराए जाने को गलत ठहराया गया था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस याचिका को जनहित याचिका नहीं माना और चलने लायक नहीं कहते हुए याचिका खारिज कर दिया।

याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डबल बेंच में चल रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और पर्यटन मंडल व समाज कल्याण विभाग के वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में बताया गया है कि राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या जाने वालों के लिए

विशेष रेल चलाई जा रही। पर्यटन मंडल व समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्य को किया जा रहा। इस योजना को चलाने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया, इसके अलावा अलग से अधिसूचना जारी की गई। इस मामले में याचिका पर पहले सुनवाई हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री रामलीला दर्शन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राम भक्तों को साय सरकार की ओर से अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन मुफ्त में कराया जा रहा है। योजना के तहत सरकार ट्रेन बुक कर राम भक्तों को अयोध्या ले जा रही है। साथ ही रामभक्तों के रहने खाने के भी इंतेजाम कर रही है। इस योजना के तहत 5 मार्च को रायपुर रेलवे स्टेशन से पहली फ्री आस्था स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ट्रेन में छत्तीसगढ़ के 850 तीर्थ यात्रियों अयोध्या रामलला दर्शन के लिए रवाना किए गए थे।

ट्रेन रद्द करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रेलवे से सवाल

जब मालगाड़ी चल सकती है तो यात्री ट्रेन क्यों नहीं : हाईकोर्ट

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द कर रहा है। कोरोना के दौरान शुरू हुआ ट्रेन कैंसिल का सफर आज भी जारी है। इस मामले को लेकर बिलासपुर में रहने वाले कमल दुबे ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई।

बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पिछले 4 साल से ट्रैक मेंटेनेंस, सिगनलिंग और दोहरी, तीसरी लाइन निर्माण को लेकर यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है। अचानक ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की इसी समस्या पर हाईकोर्ट का ध्यान खींचने बिलासपुर के रहने वाले कमल दुबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है।

कमल दुबे ने याचिका में बताया कि जिस रूट पर यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है उसी रूट पर उसी दिन माल गाड़ियां चलाई जाती हैं। साथ ही ये भी कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ही ट्रेनों को ज्यादा रद्द किया जा रहा है जबकि देश के दूसरे जोन में यात्री ट्रेन आसानी से चलाई जा रही है जबकि मेंटेनेंस का काम वहां भी किया जा रहा है।

ट्रेन कैंसिल पर लगाई गई जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए रेलवे के वकील से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मालगाड़ियां चलने पर रेल लाइन को कोई नुकसान ना हो और यात्री गाड़ी चलने पर खतरा हो सकता है। यदि ऐसा कोई नियम है तो फिर रेलवे बोर्ड इसका जवाब दें। कोर्ट ने ये भी कहा कि- जब मालगाड़ी चलाई जा सकती है तो यात्री गाड़ी के चलने से क्या परेशानी हो सकती है। रेलवे मालगाड़ियों को ज्यादा महत्व देता है या फिर यात्री गाड़ियों को महत्व देना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे से 21 मार्च को मामले में जवाब पेश करने का आदेश दिया।

अंतिम दौर में बोर्ड परीक्षा, 23 मार्च से शुरू होगा मूल्यांकन

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो गया है। एक दिन पहले बुधवार को 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है। कल 21 मार्च गुरुवार को कक्षा 12वीं की परीक्षा खत्म होगी। कबीरधाम जिले में इस बार 20 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। अब परीक्षा के बाद उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन का दौर शुरू होगा।

कबीरधाम जिले के आदर्श कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के माशिमं ने उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन केन्द्र बनाया है। यहां कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र अध्यक्ष आरपी सिंह ने बताया कि प्रथम चरण के तहत माशिमं ने लगभग 40 हजार उत्तरपुस्तिका आई हैं। इन उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 23 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए करीब 250 से अधिक मूल्यांकनकर्ता शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी।

मूल्यांकन केन्द्र में गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर साल उनके केन्द्र में लगभग एक लाख से अधिक उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किया जाता है। माशिमं द्वारा अलग-अलग चरण में उत्तर पुस्तिका भेजी जाती है। गौरतलब है कि माशिमं की बोर्ड परीक्षा एक मार्च से शुरू हुई है। बोर्ड द्वारा 15 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने लक्ष्य रखा गया है। ताकि, जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी किया जा सके। उम्मीद है कि मई माह में परीक्षा परिणाम जारी हो जाएंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आधी रात को ओड़िसा बॉर्डर पहुंचे एसडीएम, किया निरीक्षण

कोंडागांव। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतिबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले के सीमावर्ती इलाकों मे चेकपोस्ट बनाए गए हैं। जहां पुलिस, प्रशासन एवं वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ओड़िसा की ओर से आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक कर उनकी जांच की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार देर रात केशकाल एसडीएम अंकित चौहान ने ओड़िसा बॉर्डर से लगे गांव कौंदकेरा, ठेंगापारा, बांसकोट एवं गम्हरी में बनाए गए चेकपोस्ट पहुंच कर आकस्मिक निरीक्षण किया। जहां उन्होंने ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को आने जाने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही होने की शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान उनके साथ विश्रामपुरी थाना प्रभारी संजय वट्टी एवं बांसकोट चौकी प्रभारी विनोद नेताम भी मौजूद रहे।

पुरंगेल-गमपुर मुठभेड़ में मारे गये नक्सलियों की हुई पहचान

दंतेवाड़ा। थाना किरन्दुल क्षेत्रान्तर्गत पुरंगेल गमपुर के जंगल में नक्सल गश्त सर्च अभियान के दौरान 19 मार्च को हुए मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान मौके से एक पुरुष नक्सली व एक महिला नकसली का शव बरामद हुआ था। मारे गये महिला नक्सली की पहचान डोडी लक्खे उर्फ माड़वी लक्खे मिलिट्री प्लाटून नंबर 24 सदस्य/केरलापाल अध्यक्ष/एसीएम (एरिया कमेटी सदस्य) के रूप में हुई है, जिस पर 5 लाख रूपये का ईनाम घोषित है। मारी गई महिला नक्सली विभिन्न नक्सली वारदातों में शामिल थी एवं उसके विरुद्ध जिला दंतेवाड़ा एवं सुकमा में कुल 5 अपराध दर्ज है। दूसरे मारे गये पुरूष नक्सली की पहचान एक लाख का ईनामी लच्छू निवासी गमपुर गमपुर ग्राम जनताना सरकार अध्यक्ष के रूप में की गई है। जिसपर थाना किरंदुल में 01 अपराध दर्ज है।

ओपन स्कूल परीक्षा में शिक्षक करा रहे थे सामूहिक नकल

सारंगढ़/बिलाईगढ़। ओपन स्कूल के हिन्दी विषय की परीक्षा में सामूहिक नकल के मामले में 9 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई द्वारा की गई कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सामूहिक नकल प्रकरण पर जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है, उनमें दयासागर प्रधान, व्याख्याता, शाउमावि सांकरा, अंजली सिदार, सहायक शिक्षक (एलबी) प्राशा कनकीडीपा, लोकनाथ साहू सहायक शिक्षक, (एलबी) प्राशा भंवरपुर, युवधेश पटेल, सहायक शिक्षक (एलबी) प्राशा बुन्देली, हेमंत पटेल, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, बरमकेला, दिलीप सिदार, सहायक शिक्षक (एलबी) प्राशा हास्टलपारा बरमकेला, श्यामा सिदार, प्रधान पाठक प्राशा पुरैना, गिरधारी पटेल, सहायक शिक्षक विज्ञान, शाकउमावि बरमकेला और चन्द्रशेखर वैष्णव व्याख्याता शाकउमावि बरमकेला शामिल हैं। परीक्षा केन्द्र शाकउमावि बरमकेला में ओपन स्कूल की कक्षा 12वीं की हिन्दी विषय की परीक्षा के दौरान सभी कमरों में सामूहिक नकल चल रही थी।

शिक्षा व्यवस्था बदहाल, पैसे लेकर पास कराने का आरोप

खैरागढ़। जिले में एक के बाद एक बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मामले सामने आ रहा है। स्वामी आत्मानंद कन्या शाला में दसवी परीक्षा में नकल का मामला शांत हुआ नहीं कि रश्मि देवी महाविद्यालय में भी वार्षिक परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में जांच का हवाला देकर जिम्मेदार मौन हैं। एक और ताजा मामला खैरागढ़ के आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से निकलकर सामने आया है। आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के छात्रों ने सेंटर के डायरेक्टर राजेश देवांगन पर पैसे लेकर छात्रों को पास करने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। छात्रों ने बताया, जो छात्र पैसा नहीं देते उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें फेल भी कर दिया जाता है। इन मामलों में जिम्मेदार मौन हैं। बता दें कि आईआईटी ग्रुप खैरागढ़ डॉ. सीवी रमन यूनिवर्सिटी से संबंधित संस्था है, जो स्थानीय रश्मि देवी नगर खैरागढ़ शहर में संचालित है। यहां छात्रो को डीसीए और पीजीडीसीए की रेगुलर क्लास दी जाती है।

जंगल में लगी थी जुआरियों की महफिल, आठ गिरफ्तार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सोनादुला के लीलागर नदी के किनारे जुआ खेल रहे आठ जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पांच बाइक, एक ब्रेजा कार और 70 हजार 760 रुपये, 52 पत्ती ताश को मौके पर से जब्त किया गया है। सभी आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3,2 के तहत कार्रवाई की गई है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी अनुसार, एसपी विवेक शुक्ला ने जिले में चल रहे जुआ/सट्टा खिलाने वालो के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जांजगीर सायबर टीम और अकलतरा पुलिस को सूचना ग्राम सोनादुला के लीलागर नदी के किनारे कुछ लोग ताश-पत्ती से रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। मौके पर से आठ आरोपियों को जुआ खेलते पकड़ा गया है। सभी आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्र और अन्य जिले से हैं।

1952 से लेकर 1971 तक बस्तर लोकसभा सीट पर निर्दलियों का रहा वर्चस्व

जगदलपुर। लोकतंत्र के पर्व का आगाज लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ हो गया है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा, पहले चरण का मतदान एकमात्र आदिवासी बाहुल्य आरक्षित सीट बस्तर लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को होगा, इसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य आरक्षित सीट बस्तर लोकसभा का इतिहात बड़ा रोचक है, जिस बस्तर को आदिवासी-पिछड़ा माना जाता है, वहां की जनता की जागरूकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद वर्ष 1952 से लेकर वर्ष 1971 तक बस्तर लोकसभा सीट के चुनावों में यहां निर्दलीय जीतकर आते रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने की परिपाटी वर्ष 1952 के पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा को 83.05 प्रतिशत वोट के रिकार्ड जीत के साथ जुड़ा है, इस रिकॉर्ड को आज तक कोई उम्मीदवार तोड़ नहीं पाया है। जबकि निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुरती क्रिसटैय्या को मात्र 16.95 प्रतिशत वोटों से संतोष करना पड़ा था। मुचाकी कोसा को 1,77,588 और सुरती को 36,257 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत-हार का अंतर 66.09 प्रतिशत वोटों का था। इसके बाद अब तक लोकसभा चुनाव के इतिहास में अधिकतम वोट कांग्रेस के मनकूराम सोढ़ी के नाम पर है, जिन्हे 1984 के चुनाव में उन्हें 54.66 प्रतिशत वोट मिले थे।

आदिवासी बाहुल्य बस्तर लोकसभा सीट में निर्दलीय उम्मीदवारों के वर्चस्व को वर्ष 1980 में कांग्रेस ने तोड़ा, लेकिन यह मात्र 02 चुनावों तक ही सीमित रहा। वर्ष 1991 में पुनः निर्दलिय प्रत्याशी महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद भाजपा के बलीराम कश्यप इसके बाद 20 वर्षों तक अनवरत बस्तर लोकसभा सीट पर कमल खिलते रहे, लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में दीपक बैज ने भाजपा के बैदूराम कश्यप को शिकस्त दी और बस्तर लोकसभा सीट फिर कांग्रेस के कब्जे में आ गई। बस्तर लोकसभा

सीट के लिए मतदान में करीब एक माह का समय रह गया है। भाजपा ने यहां से महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। महेश लंबे समय तक संघ में सक्रिय रहे और विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री बने। उन्होने बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच का गठन कर संभागीय संयोजक के रूप में सक्रिय रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने आज दिनांक तक अपना प्रत्याशी नहीं तय किया है। हालांकि कांग्रेस से दीपक बैज और कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी के नाम की चर्चा है।

उल्लेखनिय है कि वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और पहली बार वर्ष 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए। उस समय देश में लोकसभा की कुल 489 सीटें थीं। इनमें कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस बस्तर की लोकसभा सीट हार गई थी। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरती किसतिया को 141331 वोटों से हराया था। निर्दलीय उम्मीदवार मुचाकी कोसा ने 177588 वोट हासिल किए, वहीं सुरती को महज 36257 वोट ही मिल पाए थे। हालांकि वर्ष 1957 में हुए अगले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। पार्टी ने सुरती पर भरोसा जताया और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को 99277 वोटो से शिकस्त दी थी। वर्ष 1952 से लेकर 1999 तक यह सीट मध्यप्रदेश में आती थी, वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद यह छत्तीसगढ़ में आ गई। वर्ष 1957 में बड़ी जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस का आगे के लोकसभा चुनावों में सूपड़ा साफ हो गया और वर्ष 1962, 1967, 1971 और 1977 में लगातार कांग्रेस की हार हुई। वर्ष 1962 में यह स्थिति हो गई कि कांग्रेस निर्दलीयों के मुकाबले तीसरे नंबर पर सिमट गई। वर्ष 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार जे सुंदरलाला ने जनसंघ प्रत्याशी आर झादो को बुरी तरह हराया। वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी गिरी की वह लुढ़ककर पांचवें स्थान पर पहुंच गई। वर्ष 1971 में बस्तर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी लम्बोदर बलियार जीते और अगला चुनाव कांग्रेस से लड़े, लेकिन भारतीय लोक दल प्रत्याशी दृगपाल शाह केसरी से हार गए। लगातार 4 लोकसभा चुनावों में मिली हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। इससे उबरने के लिए 1980 में कांग्रेस ने नए उम्मीदवार लक्ष्मण कर्मा को मैदान में उतारा। कांग्रेस का यह फैसला सही निकला और कर्मा ने जनता पार्टी के उम्मीदवार समारू राम परगानिया को हराया। इस जीत के बाद कांग्रेस ने वर्ष 1991 तक लगातार तीन चुनावों में जीत हासिल की। वर्ष 1984 से 1991 तक कांग्रेस ने मंकूराम सोड़ी को टिकट दिया, मानकूराम सोढ़ी मजबूत नेता साबित हुए। उन्होंने वर्ष 1984 में उन्होंने सीपीआई के महेंद्र कर्मा, 1989 में भाजपा के संपत सिंह भंडारी और 1991 में फिर भाजपा प्रत्याशी राजाराम तोडेम पर जीत दर्ज की। हालांकि 1996 में कांग्रेस उम्मीदवार मानकूराम को निर्दलीय महेंद्र कर्मा ने 14 हजार वोटों से हरा दिया। वर्ष 1998 में भाजपा ने यहां से जीत का खाता खोला और 2014 तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाये रखा। वर्ष 1998 से लेकर 2011 तक भाजपा के टिकट पर बलिराम कश्यप ने लगातार चार बार जीत हासिल की। वर्ष 2011 में उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव करवाए गए, जिसमें उनके पुत्र दिनेश कश्यप जीते और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वर्ष 2014 के चुनाव में भी दिनेश कश्यप ने अपनी जीत को बरकरार रखा, फिर वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप पर चित्रकोट विधायक रहे दीपक बैज 38982 वोटों से जीत दर्ज की और बस्तर सांसद चुने गए।

संक्षिप्त समाचार

समस्त पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे

रायपुर। लोकसभा चुनाव के संचालन के लिए राज्य सरकार के समस्त पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे और आयोग के नियंत्रण में रहेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की ओर से मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटलनगर से इस आशय के अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के प्रावधान के अनुसरण में और भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र में दिए गए निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, लोकसभा चुनाव के संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से पदाभिहीत समस्त पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना दिनांक से प्रारंभ होकर एवं ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे और ऐसे पुलिस अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

दो दिन के दौरे पर आ रहे सचिन पायलट जांजगीर में करेंगे प्रचार-प्रसार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन के लौटने के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट दो दिन के दौरे पर कल रायपुर आ रहे हैं। वे कल 11.55 बजे इंडियो के नियमित विमान से रायपुर पहुंचेंगे। यहां से वे कार के द्वारा पलारी, कसडोल, गिदौरी, रामगढ़ होकर जांजगीर जाएंगे। जहां कार्यकताओं की बैठक और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर में स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करने के बाद रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। 22 मार्च की सुबह वे बिलासपुर से रवाना होकर बिल्हा, नांदघाट, सिमगा होते हुए रायपुर पहुंचेंगे जहां राजीव भवन में रायपुर लोकसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर शाम को 4.30 बजे इंडियो के विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगे।

राज्यपाल ने नरेंद्र शुक्ल व आलोक को दिलाई राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने बुधवार को राजभवन के दरबार हाल में आयोजित समारोह में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल एवं श्री आलोक चन्द्रवंशी को राज्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत, श्री सरजियस मिंज, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त श्री एस. के. तिवारी, श्री ए.के. अग्रवाल, श्री मोहन पवार, श्री मनोज त्रिवेदी, श्री धनवेंद्र जायसवाल, राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री गोपाल वर्मा सहित श्री आई.पी. मिश्रा, श्री राकेश चतुर्वेदी, डॉ. सुरेंद्र शुक्ल, श्री एल.एन. तिवारी, श्री अंजनी कुमार शुक्ल, श्री डी.सी. पाण्डेय, श्री अनुराग दीवान एवं नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों के परिजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

595 महिलाओ को दिया गया स्वावलंबी बनाने प्रशिक्षण

रायपुर। समर्थ जनकल्याण समिति के वीआईसी प्रशिक्षण भागीदार द्वारा 595 महिलाओ को स्वावलंबी बनाने के लिए 4 जनवरी से प्रशिक्षण दिया जा रहा था जिसका कल समापन हुआ। इस अवसर पर सभी महिलाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई द्वारा प्रशिक्षण प्रशस्त्रीय पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय तिवारी, ग्राम सेवा अध्यक्ष एवं श्री भागीरथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रमुख डॉ. उदय भान सिंह चौहान, पंडित विकास शास्त्रीय, समर्थ जनकल्याण समिती के अध्यक्ष डा. जया द्विवेदी, बसंत जैन, समिति के प्रमुख सलाहकार एव प्रदेश मीडिया प्रमुख, किसान कल्याण महासंघ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री घनश्याम यादव, संरक्षक ललिता यदु, समूह के प्रदेश अध्यक्ष बिंदु यादव, प्रकाश शर्मा, समिति की सक्रिय सदस्य राजलक्ष्मी, मोहन ब्रल्याणी, सुषमा सावंत, नगर निगम से आरती सिंग आदि उपस्थित थे।

कांग्रेस को नहीं मिल रहा प्रत्याशी : अमर अग्रवाल

पूर्व मंत्री अमर ने कहा- प्रमुख नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, भिलाई से कैंडिडेट लाना स्थानीय नेताओं का दुर्भाग्य

बिलासपुर। पूर्व मंत्री और लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को घोषणा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के सभी स्थानीय प्रमुख नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। भिलाई से यहां प्रत्याशी को चुनाव लड़ने पर विचार किया जा रहा। ये स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का दुर्भाग्य है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेसी बौखला गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि प्रदेश की जनता किसके साथ है। 1996 से लगातार भाजपा बिलासपुर लोकसभा चुनाव जीत रही है। जीत का अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे।

कांग्रेस के नहीं खोले 5 पत्ते

बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने प्रदेश की सभी 11 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिसमें बिलासपुर से बीजेपी ने पूर्व विधायक तोखन साहू को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं कांग्रेस अब तक 11 में से 6 सीटों पर ही नाम तय कर पाई है। 5 बची हुई सीटों में बिलासपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। जहां कैंडिडेट तय होना बाकी है।

2014 और 2019 में भी भाजपा ने मारी थी बाजी

पिछले दो लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां दोनों बार भाजपा ने अपना परचम लहराया है। जिसमें 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के लखनलाल साहू ने जीत दर्ज की थी। इनके सामने कांग्रेस ने वरिष्ठ नेत्री करुणा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था। दोनों प्रत्याशियों में जीत का अंतर 1 लाख 76 हजार 436 वोटों का रहा। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अरुण साव ने बाजी मारी थी। जिसके सामने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव थे। जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को 1 लाख 41 हजार 763 वोटों से हराया था।

सरोज पांडेय को बाहरी प्रत्याशी बताने पर मंत्री लखनलाल ने कांग्रेस से पूछा- ज्योत्सना महंत कहां कोरबा की हैं

रायपुर। कांग्रेस द्वारा कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय को बाहरी बताए जाने पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सरोज पांडेय कोई बाहर की नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी हैं।

ज्योत्सना महंत कहां कोरबा की हैं। वह भी तो बाहर से ही आई हैं। हम कोरबा के रहने वाले हैं और वहां के कार्यकर्ताओं में और जनता में भारी उत्साह है। सरोज पांडेय लाखों वोटो से जीतने वाली हैं। ज्योत्सना महंत ने सांसद रहते हुए 5 साल कोई काम नहीं किया है।

मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि महंत ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है वो है भ्रष्टाचार। मुझे कोरबा से विधायक बने 3 महीना हुआ है भाजपा ने डीएमएफ फंड में 35, 37 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। इन लोगों ने केवल एक ही काम किया है, वो है कमीशनखोरी।

बता दें कि कोरबा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय को प्रत्याशी बनाया है। इनके सामने कांग्रेस ने वर्तमान सांसद ज्योत्सना महंत को रिपीट किया है।

कांग्रेस के नेताओं को धमका रही भाजपा : चरणदास महंत

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ का सियासी पारा उबाल पर है। भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप के साथ जुबानी जंग जारी है। इन सबके बीच नेता प्रतिपक्ष चरणदास मंहत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि भाजपा कांग्रेस के नेताओं को डराकर अपने पार्टी में शामिल होने कह रही है। इतना ही नहीं नेताप्रतिपक्ष ने 2 लोगों का नाम भी बताया है।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत ने का बड़ा बयान देते हुए कहा, बीजेपी हमारे नेताओं को डरा धमका रही है। मैं खुलकर नाम लेकर बता रहा हूं। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पर लगातार बीजेपी दबाव बना रही है। उन पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है, नहीं तो झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

आगे उन्होंने कहा, पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया को भी डराया गया। चिट्ठी और बयान उसी का हिस्सा है। कांग्रेस के दोनों नेता से कहा जा रहा कि बीजेपी में शामिल हो जाओ या कांग्रेस के खिलाफ षडयंत्र करो। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि जांजगीर से लेकर तमाम लोकसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं।

सूचना के अधिकार के तहत ईओडब्ल्यू से ली जा सकती है जानकारी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया था। इस अधिसूचना के बाद कोई भी ईओडब्ल्यू से सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी नहीं ले सकता था। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ चिरमिरी में रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

आरटीआई कार्यकर्ता ने 15 नवंबर 2016 को सूचना के अधिकार का एक आवेदन प्रस्तुत कर ईओडब्ल्यू से जानकारी मांगी। संस्था ने इस आधार पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार ने उन्हें सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया है। इस मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में सुनवाई के बाद यह जानकारी मिली कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 की उपधारा 4 में उल्लेख है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से किसी भी संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की जांच करती है, इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने आरटीआई में शामिल करने का दिया आदेश- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग 7 नवंबर 2006 को जो अधिसूचना जारी कर ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त किया, वह त्रुटि पूर्ण है। भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना देने से संस्था को मुक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इस आदेश के तीन सप्ताह के अंदर सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना में जरूरी संशोधन करें। ईओडब्ल्यू को सूचना के अधिकार के दायरे में लाए।

हमर राज पार्टी का बस्तर संसदीय सीट पर फोकस

भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने मजबूत आदिवासी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में

जगदलपुर। हमर राज पार्टी में बस्तर संसदीय सीट पर उम्मीदवार उतारने को लेकर बैठक जारी है। हमर राज पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी सीटों में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए हमर राज पार्टी मजबूत आदिवासी चेहरे को बतौर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी में उम्मीदवार के नाम को लेकर बस्तर के मुरिया सदन में विचार विमर्श चल रहा है।

हमर राज पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा, हमर राज पार्टी का उद्देश्य आदिवासी समाज को जगाना है। दोनो ही राष्ट्रीय पार्टियों ने समाज को हर बार अंधेरे में रखा है। आज भी आदिवासी अपने हक की लड़ाई को लेकर आंदोलनरत हैं। इसी बात को लेकर समाज को जगाने के लिए पार्टी मैदान में उतारी है।

अरविंद नेताम ने कहा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बैठकें की जा रही है। इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा जारी है। लगातार अलग अलग स्थानों में बैठक करके सब का मन टटोला जा रहा है। आगामी 2-3 दिनों में एक कोर कमेटी की बैठक करके उम्मीदवार का नाम उजागर किया जायेगा।

अरविंद नेताम ने कहा, इस पार्टी का राजनीतिक मैदान में उतरने के पीछे का कारण यह है कि देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टी चुनाव के दौरान काफी जोरों से आदिवासियों की बात तो करती है। लेकिन संविधान में जो कानून आदिवसियों के लिए बनी है, उसमें कभी सुधार नहीं किया, इसी कारण समस्या बढ़ रही है। बस्तर में पेशा कानून है, लेकिन उदारीकरण भी बस्तर में है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला आकर सभी संसाधनों को सरकार से मिलकर दोहन करेंगे। यही पार्टी बनाकर समाज को जगाने का टेस्टिंग टाइम है। बस्तर लोकसभा संसदीय सीट पर एक तरफ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार कर प्रचार प्रसार तेज कर दिया हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जारी है। जिसके बाद हमर राज पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी सीटों में अपने प्रत्याशियों को लेकर बैठक तेज कर दी है।

कांग्रेस प्रत्याशी महंत के साथ दिखे विनय जायसवाल

कोरबा सांसद ज्योत्सना ने कांग्रेस में गुटबाजी से किया इनकार

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कोरबा सांसद और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जिले के दौरे पर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस से निलंबन वापस लिए जाने के बाद विनय जायसवाल उनके साथ नजर आए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया।

मीडिया से मुलाकात के दौरान कोरबा से सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने दोबारा टिकट देने के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कांग्रेस के पास बेरोजगारी और महंगाई के साथ कई मुद्दे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस में गुटबाजी से भी इनकार किया और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही।

कांग्रेस पार्टी से निलंबन खत्म होने के बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस में गुटबाजी को मीडिया की देन बताया। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा, मीडिया को कांग्रेस की छोटी-मोटी बातें नजर आती है, लेकिन भाजपा की गुटबाजी उन्हें नजर नहीं आती।

विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव पर टिकट के बदले लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कांग्रेस से विनय को 6 साल के लिए निलंबित किया गया था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विनय जायसवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने आरोपों व कथन को आवेशपूर्ण आरोप लगाना बताया और क्षमा मांगी। जिसके बाद कांग्रेस ने पिछले दिनों विनय जायसवाल का निलंबन रद्द कर दिया गया। जिसके बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं।

आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई तेज 2 करोड़ से अधिक कैश और सामान जब्त

रायपुर। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों और सघन जांच की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से अब तक दो करोड़ रुपये से अधिक की अवैध धनराशि और वस्तुएं जब्त की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन और संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों की ओर से सघन जांच की कार्रवाई लगातार जारी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) की ओर से निगरानी के दौरान 19 मार्च तक 47 लाख 55 हजार रुपये की नगद धन राशि जब्त की गई हैं। इस दौरान 3896 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत आठ लाख 87 हजार रुपये है। सघन जांच अभियान के दौरान 73 लाख 17 हजार रुपये कीमत के 195 किलोग्राम मादक पदार्थ और 51 लाख 90 हजार रुपए कीमत के 840 ग्राम कीमती आभूषण और रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त 21 लाख 71 हजार रुपये से अधिक की अन्य सामग्री जब्त की गई हैं।

दुर्ग लोकसभा सीट में इस बार होगा खेला, भाजपा को दोबारा विजय पर भरोसा

दुर्ग। दुर्ग लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी लोकसभा सीटों में से एक है। यहां 1996 से बीजेपी का कब्जा है, केवल एक बार 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग सीट पर जीत दर्ज किया था। लेकिन 2019 में बीजेपी ने वापसी की और विजय बघेल यहां से सांसद निर्वचित हुए। इस बार बीजेपी ने विजय बघेल को दौबारा मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है।

विजय बघेल ने अपनी राजनीति करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी। 2000 में विजय बघेल ने भिलाई नगर परिषद का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता। उसके बाद साल 2003 में पाटन विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकट से पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद विजय बघेल बीजेपी में शामिल हुए और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यहां उनके खिलाफ कांग्रेस से भूपेश बघेल चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को करारी शिकस्त दी थी। विजय बघेल 2019 में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। अब बीजेपी ने दुर्ग लोकसभा सीट से अपने सांसद विजय बघेल पर दोबारा भरोसा जताया है। विजय बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। छग विधानसभा चुनाव 2023 में भी पाटन सीट पर दोनों चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें भूपेश बघेल ने जीत दर्ज की थी।

राजेन्द्र साहू दुर्ग जिला कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। राजेन्द्र साहू का साहू समाज में काफी पकड़ माना जाता है। वे कांग्रेस के काफी विवादित नेता भी रहे हैं। एक बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के मोतीलाल वोरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके साथ ही कांग्रेस से बगावत कर उन्होंने निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। जिसके बाद 2018 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। साल 2019 में राजेंद्र साहू भूपेश बघेल के चुनाव संचालक के तौर पर उनके साथ चुनावी अभियान में साथ रहे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का अध्यक्ष भी

बनाया गया था, लेकिन 2023 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है।

दुर्ग लोकसभा सीट का सियासी इतिहास-दुर्ग को छत्तीसगढ़ की राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देश की आजादी से लेकर 70 के दशक तक इस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन 1977 के चुनाव में यहां से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने वापसी की और 1984 में भी जीत दोहराई। फिर 1989 में यहां जनता दल ने कांग्रेस को हराकर जीत हासिल किया। लेकिन वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद 1991 में कांग्रेस ने फिर एक बार यहां से जीत दर्ज की। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सीट बीजेपी का गढ़ बन गया। 1996 से लेकर 2009 तक लगातार पांच लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की। लेकिन 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को यहां कांग्रेस ने हरा दिया। हांलाकि, 2019 में बीजेपी ने वापसी की और विजय बघेल सांसद बने।

दुर्ग लोकसभा सीट अंतर्गत विधानसभा सीटें- दुर्ग लोकसभा सीट में कुल नौ विधानसभा सीटें हैं। जिसमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग सिटी, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, बेमेतरा, साजा और नवागढ़ की सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर स्थानीयता और जातिवाद का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। खासकर साहू समाज यहां गेमचेंजर की भूमिका में है। इसके साथ ही कुर्मी और सतनामी समाज की भी प्रभुत्व है।

दुर्ग लोकसभा का मतदान प्रतिशत

2009 लोकसभा चुनाव- 55.97 फीसदी

2014 लोकसभा चुनाव- 67.74 फीसदी

2019 लोकसभा चुनाव-71.74 फीसदी

दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे- दुर्ग लोकसभा क्षेत्र शिवनाथ नदी के आसपास बसा हुआ है। यहां आद्यौगिक विकास सबसे अधिक देखने को मिलता है। यहां भिलाई स्टील प्लांट, एसीसी सीमेंट प्लांट, एल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मौजूद है। इसलिए यहां मजदूरों के मुद्दे हावी हैं। इसलिए दुर्ग लोकसभा के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी, शहरों में सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल की सुविधाएं मुख्य मुद्दे हैं। वहीं दुर्ग लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी बेरोजगारी, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा ही मुख्य मद्दे हैं। भिलाई शहर को छत्तीसगढ़ के शिक्षा का केंद्र माना जाता है। इसलिए यहां स्टूडेंट्स की उच्च शिक्षा भी बड़ा मुद्दा रहा है।

जातिगत समीकरण- दुर्ग लोकसभा के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां साहू समाज का दबदबा है। इसलिए यह साहू समाज की परंपरागत सीट भी मानी जाती है। लेकिन साहू समाज के साथ साथ यहां कुर्मी समाज और सतनामी समाज का भी धाक है। यहां जो प्रत्याशी साहू समाज के साथ कुछ हद तक कुर्मी और सतनामी वोटबैंक को साध लेता है, वह जीत जरूर हासिल करता है।

दुर्ग लोकसभा का संसदीय इतिहास

1952 में कांग्रेस के डब्ल्यू एस किरोलीकर ने जीत दर्ज कर पहले सांसद बने।

1957 में कांग्रेस के मोहन लाल सांसद बने।

1962 में फिर कांग्रेस के मोहन लाल जीते।

1967 में कांग्रेस के वी वाय तामस्कर जीते।

1971 में कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर को जीत मिली।

1977 में बीएलडी के मोहन भईया को जीत मिली।

1980 में कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर फिर सांसद बने।

1984 में कांग्रेस से चंदूलाल चंद्राकर तीसरी बार सांसद बने।

1989 में कांग्रेस से जनता दल के पुरूषोत्तम कौशिक सांसद बने।

1991 में कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर ने चौथी बार जीत दर्ज की।

1996 में बीजेपी के ताराचंद साहू को जीत मिली।

1998 में बीजेपी के ताराचंद साहू फिर जीते।

1999 में बीजेपी के ताराचंद साहू तीसरी बार जीते।

2004 में बीजेपी के ताराचंद साहू चौथी बार जीते।

2009 में बीजेपी की सरोज पांडे ने जीत दर्ज की।

2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने जीत दर्ज की।

2019 में बीजेपी के विजय बघेल ने जीत हासिल की।

विभिन्न रणनीतियां अपनाती है भाजपा

अभय कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की प्रबंधन-क्षमता में अगाध विश्वास करने वाले भाजपा प्रवक्ताओं और उनके सहोदरों की भांति टीवी-मंच पर पेश होने वाली समीक्षक-मंडली का विचार है कि मौजूदा सूरत में मोदी की तीसरी जीत को रोका नहीं जा सकता। इस दावेदारी में कितना भी एकतरफापन क्यों न हो, आज की तारीख में आकलन करने पर इसे कमोबेश ठीक माना जा सकता है। वजह यह है कि विपक्ष की प्रभावी एकता की गैरमौजूदगी में फिलहाल मोदी का पलड़ा भारी लग रहा है। विपक्ष की एकता अगर हो गई होती तो वह मोदी को रोक सकता था, पर वह एकता तो अभी आधी-अधूरी है और उसमें कई किंतु-परंतु हैं। भाजपा अलग-अलग राज्यों में विभिन्न रणनीतियां आजमाती है। हर जगह वह अपनी तरफ झुकी जातियों और समुदायों का अपनी राजनीति में टिकट वितरण के जरिये समावेशन करती है, और समाज के जो हिस्से उसके साथ नहीं हैं, उनका बहिर्वेशन करती है। हरियाणा में भाजपा खुले तौर पर जाट-विरोधी और गैर-जाटों की पार्टी बन कर उभरी है, महाराष्ट्र में उसने कई जगहों पर मराठा विरोधी चुनावी गोलबंदी की है और कर्नाटक में वह मुख्य तौर पर लिंगायतों की पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने यादव-जाटव-मुसलमान के त्रिकोण को न केवल अपनी चुनावी राजनीति से दूर रखा है, बल्कि इन तीनों समुदायों के विरोध के आधार पर उसने अपने समर्थन की मुहिम चलाई है। बिहार में भाजपा ने यादवों का बहिर्वेशन किया है। अशोका यूनिवर्सिटी के त्रिवेदी शोध केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनावों में उप्र में भाजपा ने अपने 45 फीसदी से ज्यादा टिकट ऊंची जाति के उम्मीदवारों को दिए, क्योंकि भाजपा जानती थी कि ये जातियां उसकी सर्वाधिक निष्ठावान समर्थक हैं। पार्टी हारे या जीते, ये जातियां चुनाव-दर-चुनाव भाजपा को साठ-सत्तर फीसदी के आसपास वोट करती रही हैं। अगर मोटे तौर पर मान लिया जाए कि उत्तरप्रदेश में दस फीसदी यादव हैं, दस फीसदी जाटव हैं और बीस फीसदी मुसलमान हैं, तो प्रदेश की इस चालीस फीसदी जनता को भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति से तकरीबन बहिष्कृत रखा। यह विश्लेषण भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं है। उसे भी अपनी चुनावी रणनीति बनाने का पूरा हक है।आखिरकार समाजवादी पार्टी अपने ज्यादातर टिकट केवल यादव उम्मीदवारों को देना ही पसंद करती है। मायावती भी सबसे ज्यादा टिकट जाटवों को देती हैं, हालांकि यह कहना उचित होगा कि बसपा समाज के अन्य तबकों का भी ध्यान रखती है और उसका टिकट वितरण सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रातिनिधिक प्रतीत होता है। स्पष्ट रूप से उत्तर भारत में भाजपा ऊंची जातियों, गैर-यादव पिछड़ों और गैर-जाटव दलितों की पार्टी के तौर पर उभरी है। यह आधे से अधिक हिंदू समाज की भाजपा समर्थक हिंदू एकता का नजारा है। इस हिंदू एकता का एक मकसद है सामाजिक न्याय की तथाकथित ब्राह्मण विरोधी राजनीति को हाशिये पर धकेल देना और दूसरा मकसद है मुसलमानों के वोटों की प्रभावकारिता को समाप्त कर देना। पिछले पांच साल से उत्तर भारत में मुसलमान मतदाता निष्ठापूर्वक भाजपा विरोधी मतदान करने के बावजूद चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव डालने में नाकाम रहे हैं। लोकतंत्र बहुमत का खेल है, और देश में हिंदुओं का विशाल बहुमत है। मुसलमान वोटर किसी बड़े हिंदू समुदाय के साथ जुड़ कर ही चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर भारत में मुसलमान मतदाता आम तौर पर पिछड़ी और दलित जातियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियों को समर्थन देते रहे हैं। बाकी जगहों पर वे कांग्रेस के निष्ठावान वोटर हैं। दिक्कत यह है कि कथित रूप से सेक्युलर राजनीति करने वाली इन पार्टियों को हिंदू मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने त्याग दिया है। हिंदू राजनीतिक एकता के तहत 42 से 50 फीसदी के आसपास हिंदू वोट एक जगह जमा हो जाते हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और सीता सोरेन

अजय सेतिया

शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने की खबर के साथ ही पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े की ओर से उनका स्वागत किए जाने की फोटो ने चौंकाया। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत संभालना चाहती थी, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने छोटे बेटे हेमंत सोरेन को आगे कर कर दिया। तब से सीता सोरेन की राजनीतिक विरासत की लड़ाई अपने देवर हेमंत सोरेन से है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, जिसका सीता सोरेन विरोध कर रही थी। आखिर पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के नाम पर सहमति हो गई और वह मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने बहुमत भी साबित कर दिया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस अभी भी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं।

अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन से मुलाक़ात की थी। चंपई सोरेन 18 मार्च को मुम्बई में इंडी गठबंधन की रैली में अपने साथ कल्पना सोरेन को भी लेकर गए, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि के तौर पर मंच से उनका भाषण भी हुआ। सीता सोरेन को आशंका है कि चंपई सोरेन की जगह कभी भी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पार्टी की नेता के तौर पर उभारने की कोशिश की जा रही है। सीता सोरेन ने कल्पना के इंडी एलायंस मंच से भाषण पर सवाल उठाया और झामुमो छोड़ कर भाजपा ज्वाईन कर ली। सवाल यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस परिवार की बहू को अपनी पार्टी में क्यों ले रहा है, जो खुद भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, और जिसका परिवार भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। क्या इससे नरेंद्र मोदी की परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगी? ठीक इसी तरह सवा महीना पहले आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले के आरोपी अशोक चव्हाण की भाजपा में एंट्री के साथ ही उन्हें राज्यसभा टिकट दिए जाने की घटना ने भी मोदी समर्थकों को चौंका दिया था।

इन दोनों खबरों के बीच सिर्फ 15 दिन पहले 4 मार्च को सुप्रीमकोर्ट का एक एतिहासिक फैसला आया है, जिसे आज फिर याद किया जाना जरूरी है। 4 मार्च को सुप्रीमकोर्ट की सात जजों की बेंच ने 1998 के पांच जजों के फैसले को पलट दिया था। 1998 और 2024 के दोनों फैसलों से शिबू सोरेन और उनकी पुत्रवधू दोनों का ताल्लुक है, इसलिए इन दोनों फैसलों को आज याद किया जाना जरूरी है। भाजपा को सीता सोरेन की पार्टी में एंट्री करवाने से पहले 4 मार्च 2024 के सुप्रीमकोर्ट के सात जजों की बेंच के फैसले को जरूर ध्यान में रखना चाहिए था। पहले 1998 के फैसले की बात कर लेते हैं, जिसका सीधा ताल्लुक शिबू सोरेन से है।

इसकी शुरुआत जुलाई 1993 में हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। अविश्वास प्रस्ताव में राव सरकार का गिरना तय था। अपनी अल्पमत सरकार बचाने के लिए राव ने अपने रणनीतिकारों से सांसदों का जुगाड़ करने को कहा था। उनके रणनीतिकारों गृह मंत्री बूटा सिंह, पेट्रोलियम मंत्री सतीश शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने ऐसे सांसदों से संपर्क किया, जिन्हें लालच देकर खरीदा जा सकता था। इस समय के दो प्रकरण थे, एक प्रकरण तो जनता दल के बिहार के सांसद राम लखन सिंह यादव का था। वह जनता दल छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन्हें कैश के साथ साथ नरसिंह राव ने अपनी सरकार में उर्वरक मंत्री भी बना दिया था। बाद में राम लखन सिंह के बेटे प्रकाश यादव ने नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव और भतीजे संजीव राव के साथ मिल कर 133 करोड़ का यूरिया घोटाला किया। इसमें 133 करोड़ की राशि एडवांस दे दी गई थी, जबकि यूरिया आया ही नहीं।

सीबीआई ने दो साल पहले क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के बजाए सीबीआई को फटकार दिया था। इस बीच एक बार नरसिंह राव के छोटे बेटे प्रभाकर राव की गिरफ्तारी भी हुई थी। दूसरा केस सीता सोरेन के ससुर और जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन से जुडा है। शिबू सोरेन उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे। वह सांसद भी थे और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीन और सांसद थे, शैलेन्द्र महतो, सूरज मंडल और साइमन मरांडी। इन चारों सांसदों ने नरसिंह राव सरकार बचाने के लिए 55-55 लाख रूपए रिश्वत ली थी। कैश का इंतजाम हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल और पेट्रोलियम मंत्री सतीश शर्मा ने किया था। रिश्वत का धन क्योंकि चारों सांसदों ने बैंक खातों में जमा किया था, इसलिए कोई मुकर भी नहीं सकता था। मामला सुप्रीमकोर्ट में गया, उन चारों ही सांसदों ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्वीकार किया था कि 1993 में उन्हें विश्वासमत के पक्ष में वोटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी ने धन दिया था।

इसके बावजूद सुप्रीमकोर्ट की पांच जजों की बेंच ने बहुमत के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 105(2) में सांसदों को मिले विशेषाधिकार का हवाला देकर मुकद्दमे को ही रद्द कर दिया था। सारा देश सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से दंग रह गया था। इसी तरह का एक प्रावधान अनुच्छेद 194 (2) में भी है, जो विधायकों को भी इसी तरह का विशेषाधिकार देता है। सुप्रीमकोर्ट के इस एक गलत फैसले के बाद सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने की छूट मिल गई थी। 26 साल बाद भी सुप्रीमकोर्ट के इस गलत फैसले की समीक्षा नहीं होती, अगर शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप न लगता। सीता सोरेन ने अपने बचाव में संविधान के अनुच्छेद 194 (2) में मिली छूट और सुप्रीमकोर्ट के 1998 के फैसले को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। तब जाकर 1998 के फैसले की समीक्षा की जरूरत महसूस हुई और चीफ जस्टिस ने सात सदस्यीय बेंच गठित की।

सुनवाई के दौरान मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीमकोर्ट में कहा था कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का सदन की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, इसलिए राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रिश्वत लेने के खिलाफ सीता सोरेन का मामला कानूनी दायरे में आता है। इसी चार मार्च को सुप्रीमकोर्ट की सात सदस्यीय बेंच ने 1998 का अपना फैसला पलटते हुए कहा है कि अनुच्छेद 105 (2) या अनुच्छेद 194 (2) में मिला विशेषाधिकार सदन के साझा कामकाज से जुड़े विषय के लिए है, वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी काम का हिस्सा नहीं है। सुप्रीमकोर्ट के इस फैसले से शिबू सोरेन भी दोषी करार होते हैं, और उनकी पुत्रवधू सीता सोरेन भी। सीता सोरेन को रिश्वत लेने का दोषी करार दिए जाने के सिर्फ 15 दिन बाद ही जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उनका पार्टी में स्वागत किया है, वह भाजपा की परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर सवाल खड़ा करता है। मोदी सरकार ही ने खुद सितंबर 2023 में सुप्रीमकोर्ट से 1998 के उसके फैसले को फिर से खोलने का आग्रह किया था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-37)

गतांक से आगे...

आत्मस्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में जो चित् का डूबना है, इससे अधिक मोहग्रस्त होना दूसरा नहीं कहा जाएगा और न हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन की अवस्था होती है, उसे ध्वस्तमनन के स्वरूप वाली स्थिति समझा जाता है, लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की शिला के समान भली प्रकार शान्त हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था जिसमें जाग्रत् और स्वप्नावस्था भी प्राय: चेष्टारहित होती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है। अहंभाव के क्षीण हो जाने पर शान्त, चेतन तथा भेदभाव से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है।

प्रथम बीज जाग्रत् अवस्था वह है, जो नामरहित शुद्धचेतन की भविष्यत् में घटित होने वाली, चित्त-जीव आदि नाम के शब्दार्थरूप सम्बोधन से युक्त अवस्था है। वह बीजरूप में स्थित जाग्रत-अवस्था बीज जाग्रत् नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाता की नूतन अवस्था है। अब आप जाग्रत् अवस्था की यथार्थ स्थिति सुनें। नवजात जीव के अन्तरंग में यह मैं हूँ, यह मेरा है अर्थात् मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह की दूसरी जाग्रत् अवस्था कही जाती है; क्योंकि उससे पूर्व यह भावना नहीं थी। महाजाग्रत अवस्था वह है, जिसमें यह वह व्यक्ति है, यह मैं हूँ, वह मेरी चीज है आदि भावनाएँ पूर्वजन्मों के संस्कार सहित विदित होती हैं। अप्रचलित (अरूढ़) अथवा प्रचलित (रूढ़) एवं तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जाग्रत् अवस्था में होती है, वह जाग्रत् स्वप्न कही गयी है। एक चन्द्रमा की जगह दो चन्द्रमाओं का, सीप में चाँदी का तथा मृग-मरीचिका में (बालू में) जल का आभास होना इत्यादि (जाग्रत् अवस्था में) अभ्यास को प्राप्त हुए जाग्रत-स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं।

क्रमशः ...

विश्व वानिकी दिवस

बाल मुकुन्द ओझा

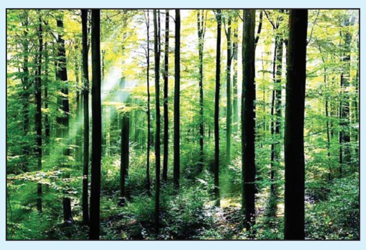

विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। यह दुनियाभर में लोगों को वनों की महत्ता तथा उनसे मिलने वाले अन्य लाभों की याद दिलाने के लिए पिछले 30 वर्षों से मनाया जा रहा है। विश्व वानिकी दिवस का उद्देश्य है कि विश्व के सभी देश अपनी वन-सम्पदा और वनों को संरक्षण प्रदान करें। भारत में वन-सम्पदा पर्याप्त रूप से है। भारत में 657.6 लाख हेक्टेयर भूमि (22.7 प्रतिशत) पर वन पाए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत 19.39 प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। गत नौ वर्षों में 2.79 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास की भेंट चढ़ गये जबकि 25 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रत्येक साल घट रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा वन-सम्पदा है उसके बाद क्रमश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के 33.3 प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए।

यूएनईपी के मुताबिक, दुनिया में 50-70 लाख हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष बंजर हो रही है वहीं भारत में ही कृषि-योग्य भूमि का 60 प्रतिशत भाग तथा आकर्षित भूमि का 75 प्रतिशत गुणात्मक ह्रास में परिवर्तित हो रहा है। भारत में पिछले नौ सालों में 2.79 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र विकास की भेंट चढ़ गए जबकि यहां पर कुल वन क्षेत्रफल 6,90,899 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वन-भूमि पर उद्योग-धंधों तथा मकानों का निर्माण, वनों को खेती के काम में लाना और लकड़ियों की बढ़ती माँग के कारण वनों की अवैध कटाई आदि वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारण हैं। जंगल हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं जो हमारे पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक स्थिति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों से मानव समुदाय को अनेक बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जिनमें स्वच्छ जल, वन्य प्राणियों के रहने के लिए स्थान, लकड़ी, भोजन, फर्नीचर, कागज, सुन्दर परिदृश्य सहित अनेक पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। पेड़, कार्बन डाइ आक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी मानव जाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। एक पेड़ अपनी पूरी उम्र के दौरान प्रकृति और मनुष्य को कई फायदे देता है। पेड़ तापमान नियंत्रण में भी अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधा रोपण करना चाहिए।

वन और जीवन दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और मनुष्य और अन्य किसी भी प्राणी का जीवन ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकता। वृक्ष और वन भू-जल को भी संरक्षित करते हैं। जैव-विविधता की रक्षा भी वनों की रक्षा से ही संभव है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए बहुमूल्य वनौषधियां हमें जंगलों से ही मिलती हैं। दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली की वजह से प्राकृतिक वनों पर मानव समाज का दबाव बढ़ता जा रहा है।

दुनिया के सबसे झगड़ालू पड़ोसी से कैसे निपटें?

राजेश बादल

अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने फिर विवाद को तूल दिया है। वह कहता है कि समूचा अरुणाचल उसका है। बीते पांच साल में उसने इस खूबसूरत भारतीय प्रदेश के बत्तीस स्थानों के नाम ही बदल दिए हैं। सदियों से चले आ रहे भारतीय नामों को नकारते हुए चीनी भाषा मंदारिन और तिब्बती भाषा के ये शब्द वहां सरकारी तौर पर मान लिए गए हैं। अब चीन कहता है कि अरुणाचल का नाम तो जंगनान है और वह चीन का अभिन्न हिस्सा है। इस तरह से उसने एक स्थायी और संभवत: कभी न हल होने वाली समस्या को जन्म दे दिया है।

जब-जब भारतीय राजनेता अरुणाचल जाते हैं, चीन विरोध दर्ज कराता है. भारत ने दावे को खारिज करते हुए चीन के रवैये की आलोचना की है। उसने कहा है कि नाम बदलने से वह क्षेत्र चीन का कैसे हो जाएगा। अरुणाचल में अरसे से लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाती रही हैं और वह भारत का अभिन्न अंग है। दोनों विराट मुल्कों के बीच सत्तर साल से यह सीमा झगड़े की जड़ बनी हुई है। क्या संयोग है कि 1954 में जब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया और दोनों देशों के बीच दो बरस तक एक रूमानी दोस्ती सारा संसार देख रहा था, तो उन्हीं दिनों यही पड़ोसी तिब्बत के बाद अरुणाचल को हथियाने के मंसूबे भी पालने लगा था।

इसी कारण 1956 आते-आते मित्रता कपूर की तरह उड़ गई और चीन एक धूर्त-चालबाज पड़ोसी की तरह व्यवहार करने लगा। तब से आज तक यह विवाद रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत और चीन के पास सीमा पर बैठकों का अंतहीन सिलसिला है, एक बड़ी और एक छोटी जंग है, अनेक खूनी झड़पें हैं और कई अवसरों पर कड़वाहट भरी अंताक्षरी।

असल प्रश्न है कि आबादी में भारत के लगभग बराबर और क्षेत्रफल में लगभग तीन गुना बड़े चीन को जमीन की इतनी भूख क्यों है और वह शांत क्यों नहीं होती? उसकी सीमा से चौदह राष्ट्रों की सीमाएं लगती हैं। गौर करने की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक देश के साथ उसका सीमा को लेकर झगड़ा चलता ही रहता है। यह तथ्य संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत जानकारी का हिस्सा है। जरा देशों के नाम भी जान लीजिए। यह हैं-भारत, रूस, भूटान, नेपाल, म्यांमार, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, वियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। इन सभी के साथ चीन की सीमा को लेकर कलह की स्थिति बनी हुई है। बात यहीं समाप्त नहीं होती।

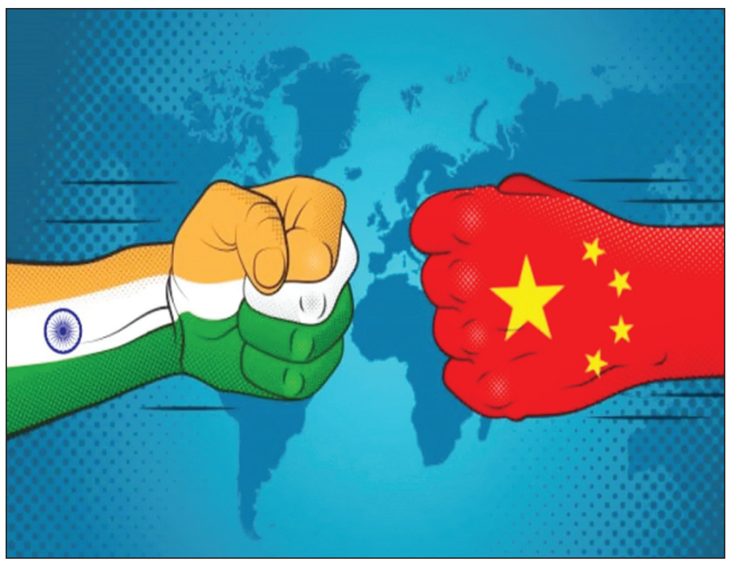

नौ राष्ट्रों की जमीन या समंदर पर भी चीन अपना मालिकाना हक जताता है। इन नौ देशों में जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, उत्तर कोरिया, वियतनाम और कम्बोडिया जैसे राष्ट्र हैं। इस तरह कुल तेईस देशों से उसके झगड़ालू रिश्ते हैं। इस नजरिये से चीन संसार का सबसे खराब पड़ोसी है। इस सूची में रूस, पाकिस्तान, नेपाल, उत्तर कोरिया और म्यांमार के नाम देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे लेकिन यह सच है।

रूस से तो 55 साल पहले वह जंग भी लड़ चुका है। जापान से भी उसकी दो जंगें हुई हैं। इनमें लाखों चीनी मारे गए थे। ताइवान से युद्ध की स्थिति बनी ही रहती है। वियतनाम से स्प्रैटली और पेरासील द्वीपों के स्वामित्व को लेकर वह युद्ध लड़ चुका है। फिलीपींस ने पिछले साल दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए चीन के सारे बैरियर तोड़ दिए थे। नेपाल और भूटान अपनी सीमा में अतिक्रमण के आरोप लगा ही चुके है। उत्तर कोरिया के साथ यालू नदी के द्वीपों पर चीन का संघर्ष छिपा नहीं है। सिंगापुर में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से चीन के संबंध सामान्य नहीं हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री भी दक्षिण चीन महासागर के बारे में अनेक बार चीन से टकराव मोल ले चुके हैं।

अब आते हैं भारत और चीन के सीमा विवाद पर। भारत ने तो चीन को दिसंबर 1949 में ही मान्यता दे दी थी। इसके बाद 1950 में कोरियाई युद्ध में शुरुआत में तो हमने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन बाद में हम अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थ बने और चीन का संदेश अमेरिका को दिया कि यदि अमेरिकी सेना यालू नदी तक आई तो चीन कोरिया में अपनी सेना भेजेगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में चीन को हमलावर करार देने का प्रस्ताव आया तो भारत ने चीन का समर्थन किया लेकिन चीन ने भारत की सदाशयता को नहीं समझा।

इसके बाद भी 1954 तक भारत और चीन मिलकर नारा लगा रहे थे-हिंदी, चीनी भाई-भाई. भारत ने तिब्बत के बारे में चीन से समझौता किया, लेकिन चीन की नजर भारतीय सीमा पर जमी रही। मगर, दो साल बाद स्थितियां बदल चुकी थीं। दिसंबर 1956 में प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने तीन-तीन बार प्रधानमंत्री नेहरूजी से वादा किया कि वे मैकमोहन रेखा को मान लेंगे पर तिब्बत में 1959 की बगावत के बाद दलाई लामा की अगुआई में 13 हजार तिब्बतियों ने भारत में शरण ली।

यहां उनका शानदार स्वागत हुआ। इसके बाद ही चीन के सुर बदल गए। भारत से मौखिक तौर पर मैकमोहन रेखा को सीमा मान लेने की बात चीन करता रहा, पर उसके बारे में कोई संधि या समझौता नहीं किया। उसने भारत सरकार को जहर बुझी चिट्ठियां लिखीं। नेहरूजी को कहना पड़ा कि चीन को अपने बारे में बड़ी ताकत होने का घमंड आ गया है। इसके बाद 1962 तक की कहानी लद्दाख में धीरे-धीरे घुसकर जमीन पर कब्जा करने की है। 1962 में तो वह युद्ध पर ही उतर आया।

उसके बाद की कहानी अविश्वास, चीन की दबे पांव भारतीय जमीन पर कब्जा करने और अंतहीन वार्ताओं में मामले को उलझाए रखने की है। हालांकि 1967 में फिर चीन के साथ हिंसक मुठभेड़ें हुईं। तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थीं। इस मिनी युद्ध में चीन की करारी हार हुई। घायल शेर की तरह चीन इस हार को पचा नहीं सका और तब से आज तक वह सीमा विवाद पर गुर्राता रहा है। डोकलाम हिंसा में गहरी चोट खाने के बाद भी वह बदलने को तैयार नहीं है। भारत भी संप्रभु देश है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि चीन से बेहतर ही है। वह चीन की इन चालों को क्यों पसंद करे?

आज का इतिहास

1975 इथोपिया में तीन हजार साल बाद राजतंत्र समाप्त।

1980 डलास ने अपने ए हाउस डिवाइडेड एपिसोड को प्रसारित किया, जिसने जेआर को किसने गोली मारी, इस बारे में अंतरराष्ट्रीय अटकलें लगाई गईं

1990 नाम्बिया को दक्षिण अफ्रीका से आजादी मिली।

1991 अमेरिकी नौसेना के दो पनडुब्बी रोधी विमान समुद्र में टकरा गए। हादसे में सत्ताईस लोगों की मौत हो गई।

1994 ऐनी पी सिदामोन-इरिस्टॉफ़ को म्यूजियम ऑफ़ नेशनल हिस्ट्री का नया अध्यक्ष बनाया गया।

1999 71 वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर समारोह में जिसकी मेजबानी व्हॉपी गोल्डबर्ग ने की थी; शेक्सपियर इन लव, ने सर्वश्रेष्ठ चित्र जीता, रॉबर्टो बेनिग्नी और ग्वेनेथ पाल्ट्रो ने सभी के बीच मुख्य अभिनय पुरस्कार जीते।

2000 गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।

2002 ब्रिटिश छात्रा अमांडा डाउलर को सरे के वाल्टन-ऑन-थेम्स में होमफ्रॉम हीथसाइड स्कूल के रास्ते में अपहरण कर लिया गया था।

2006 एक हथौड़ा का उपयोग करने वाले एक व्यक्ति ने थाइलैंड के बैंकॉक में इरान श्राइन में फ्रा फ्रॉम की प्रतिमा को तोड़ दिया और बाद में दर्शकों द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया।

2008 वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर महासागर होने के नये साक्ष्य प्राप्त किये।

2010 अफगानिस्तान में हेलमंड प्रांत के गेरेश में हुआ एक आत्मघाती बम हमला, दस लोगों की मौत और सात घायल हो गए।

2011 त्रिपोली में आतंकवादी नेता मुअम्मर गद्दाफी के परिसर को लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की तीसरी रात के दौरान अधिक बमबारी के साथ लक्षित किया गया था जिसने गद्दाफी की पूरी आतंकवादी श्रृंखला को हिला दिया था।

2011 बोस्टन, मैसाचुसेट्स में ब्रिघम और महिलाओं के अस्पताल में सर्जन ने पहले पूर्ण चेहरे का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया।

2012 ब्रेटन के चांसलर ऑफ द एनचार्ज जॉर्ज ओसबोर्न ने 2012 के बजट में ब्रेटियन का खुलासा किया जो नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए आयकर की शीर्ष दर में कटौती करता है। यह आम ब्रिटिश लोगों के लिए महान उपहार था।

2013 ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री जूलिया गिलार्ड ने औपचारिक रूप से उन लोगों से माफी मांगी जो 1950 से 1970 के दशक के दौरान जबरन गोद लेने से प्रभावित थे।

मोदी से मुकाबले में विपक्ष कर रहा आत्मघाती गोल

अजय सेतिया

लोकसभा चुनाव में पहले दिन से भाजपा और मोदी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर प्रवेश के बाद से लोकसभा के चुनाव राष्ट्रपति प्रणाली की तरह हो गए हैं। मोदी एक लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। जब तक उनके सामने एक वैकल्पिक चेहरा नहीं होगा, तब तक विपक्ष का चांस ही दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष भले ही यह कहता रहे कि 1996 में कौन सा चेहरा था, या 1977 में कौन सा चेहरा था, तब भी तो जनता ने तख्ता पलट दिया था। तो इन दोनों वक्त की परिस्थितियों को समझना जरूरी है। 1977 का नतीजा आपातकाल के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया थी, और 1996 का नतीजा नरसिंह राव की भ्रष्ट सरकार और हिंदुत्व के उभार के कारण आया था। बाबरी ढांचा टूट चुका था, जिस कारण मुस्लिम वोटर कांग्रेस से नाराज था। एक तरफ मुस्लिमों ने कांग्रेस छोड़ कर क्षेत्रीय पार्टियों का रुख कर लिया था। दूसरी तरफ हिन्दू भाजपा की तरफ आकर्षित होने लगा था।

1996 का नतीजा कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन किसी के पक्ष में नहीं था, इसलिए यह भारतीय राजनीति का सबसे कठिन दौर था, जब दो साल बाद ही चुनाव करवाने पड़े थे। 1984 से पहले के दौर को याद कीजिए, देश के दूर दराज के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी। या 1964 से पहले का जमाना देख लीजिए जब जवाहर लाल नेहरू लोकप्रिय थे। आज से दस साल पहले तक दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में किसी से पूछते थे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाब मिलता था इंदिरा गांधी। जबकि इंदिरा गांधी की 30 साल पहले हत्या हो गई थी। भारतीय राजनीति में चेहरे का हमेशा महत्व रहा है। तमिलनाडु में एमजीआर और बाद में करुणानिधि या जयललिता, इसी तरह आंध्रप्रदेश में एनटीआर चेहरे ही थे, जो राजनीति में आते ही छा गए। विपक्ष के पास न चेहरा है, न 1977 और 1996 की तरह मुद्दा है। जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद कुछ समय के लिए एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के चेहरे थे। वाजपेयी के समय भी लेखक अखबारों में लिखते थे, वाजपेयी के बाद कौन। नेहरू, इंदिरा और वाजपेयी, इन तीनों के कार्यकाल में अखबारों और टेलीविजन की दुनिया में एक शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वह शब्द था टीना फेक्टर। टीना का फुल फार्म है, देयर इज नो एल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प ही नहीं है।

अब नरेंद्र मोदी के लिए भी वही स्थिति पैदा हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव में भारत का मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है। दस साल पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इसलिए बुरी तरह हार गई थी क्योंकि उनकी सरपरस्ती में चल रही मनमोहन सिंह सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए थे। अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि गठबंधन की राजनीति की कुछ मजबूरियां होती हैं। इसका मतलब यह था कि वह भ्रष्टाचार को अपनी सरकार की मजबूरी बता रहे थे। वहीं से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा बना, जो आज दस साल बाद भी नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। अपने दूसरे दौर के पांच सालों में मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई कि विपक्ष का कोई नेता वैकल्पिक चेहरा ही नहीं बन पाया। देश की आम जनता यह मानने लगी है कि परिवारवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा तो है ही, भ्रष्टाचार की जड़ में भी परिवारवाद है। नरेंद्र मोदी ने एक एक कर विपक्ष के सभी नेताओं को अदालत में खड़े हो कर जमानत लेने को मजबूर कर दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर पी. चिदंबरम तक सब भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर रिहा हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव

भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर रिहा हैं।

ममता बनर्जी की केबिनेट के दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। उनका भतीजा ईडी की पूछताछ के घेरे में है। अरविन्द केजरीवाल की सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचार और मनीलांड्रिंग में एक साल से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का एक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल की हवा खा चुका है, आप का एक सांसद भी शराब घोटाले में जेल में है। खुद अरविन्द केजरीवाल शराब घोटाले और जल प्राधिकरण घोटाले में ईडी की पूछताछ से बचते घूम रहे हैं। ईडी के समन की तामील न करने के केस में खुद केजरीवाल जमानत पर रिहा हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरकारी जमीन हड़पने और अवैध खदान के आरोपों में इस्तीफा देकर जेल में जाना पड़ा है। उनकी भाभी सीता सोरेन को रिश्वत मांगने के आरोप में दोषी पाया गया है। इसलिए विपक्ष जितना चाहे गठबंधन कर ले, विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है।

राहुल गांधी को मोदी का विकल्प बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनमें कोई विजन ही दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें भारतीय संस्कृति, परंपराओं और भारतीय राजनीति की कोई समझ ही नहीं है। इसकी झलक बार बार उनके भाषणों में दिखती है। नफरत की राजनीति से कोई भारतीय जनमानस में अपनी जगह नहीं बना सकता। राहुल गांधी की सारी राजनीति मोदी विरोध और उनसे नफरत पर टिकी है। भले ही उन्होंने मुम्बई में अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन भाषण में कहा कि विपक्ष की राजनीति मोदी या भाजपा के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका कोई भाषण मोदी विरोध के बिना खत्म ही नहीं होता। उन्हें इतनी सी समझ नहीं है कि मोदी ने भारतीय वोटरों के मन में अपनी जगह नेहरू और इंदिरा गांधी जैसी बना ली है। उनका विरोध सिर्फ मुद्दों पर हो सकता है, लेकिन विपक्ष एक मुद्दा उठाकर दूसरे दिन उसे भूल जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे का कानूनी प्रावधान था, विपक्ष ने भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, लेकिन उन्होंने खुद भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। अब सुप्रीमकोर्ट ने उसे अवैध ठहरा दिया है, तो विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितनी भाजपा कटघरे में खडी है, उतनी ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और आम आदमी पार्टी कटघरे में है। इसलिए इलेक्टोरल बांड भी विपक्ष का सेल्फ गोल ही है।

राहुल गांधी हो या विपक्ष का कोई भी अन्य नेता, वे मोदी पर हमले करके सिर्फ सेल्फ गोल ही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की रैली में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के हिन्दू होने और उनके परिवारहीन होने का बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया था। अब राहुल गांधी ने यह कह कर अपने खिलाफ बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया कि उनका मुद्दा हिन्दू धर्म की शक्ति के खिलाफ है। वह अपनी बात को आसान शब्दों में समझा ही नहीं पाते, अलबत्ता हिन्दू धर्म के बारे में अपने अल्पज्ञान के कारण हिन्दुओं के आक्रोश और हंसी का पात्र बन जाते हैं। जिसका हिन्दू धर्म के बारे में, जिसे सुप्रीमकोर्ट ने भारत की जीवन पद्धति कहा है, उसका बोध ही नहीं है, वह भारत की अस्सी प्रतिशत हिन्दू जनता का नेता कैसे बन सकता है। मुम्बई के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि उनका विरोध भाजपा या मोदी से नहीं है, हिन्दू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उनका विरोध उस शक्ति के खिलाफ है। हिन्दू धर्म में मां काली को शक्ति माना जाता है, मां दुर्गा को शक्ति माना जाता है, स्त्री को शक्ति माना जाता है। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि वह क्या कहना चाहते हैं, और क्या कह रहे हैं। अपने नेता के अल्पज्ञान और विजन की कमी के कारण कांग्रेस खुद ही हतोत्साहित हो चुकी है। कांग्रेस चुनाव में कहीं लड़ती हुई दिखाई ही नहीं दे रही। मल्लिकार्जुन खडगे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, सभी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ममता बनर्जी ने ठीक समय पर कहा था कि लड़ाई तब दिखाई देगी, जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी के सामने खड़े हों। लेकिन गांधी परिवार तो चुनाव लड़ने से ही भाग रहा है। सोनिया गांधी चुनावों से पहले ही राज्यसभा पहुंच गई।

खबर यह आई है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, राहुल गांधी ने सुरक्षित सीट केरल की वायनाड चुन ली है। अगर राहुल गांधी की उम्मीदवारी वायनाड से पहले अमेठी घोषित होती, तो एक संदेश निकलता कि वह भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। अब वह अमेठी से भी चुनाव लड़ें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक संदेश तो चला गया है कि गांधी परिवार उस यूपी से भाग रहा है, जो उनके परिवार का राजनीतिक आधार रहा है। मोदी के सामने चुनौती तब दिखाई देती, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खम ठोक कर समाजवादी पार्टी से आधी सीटों की मांग करती, देश में एक संदेश जाता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ों यात्राओं से कांग्रेस में मोदी को हराने का कान्फिडेंस पैदा हुआ है।

क्या जजों के लिए होनी चाहिए लक्ष्मण रेखा?

राजेश चौधरी

जजों को रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पद दिया जाना कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही संवैधानिक कोर्ट के जस्टिस को राजनीतिक पद दिए जाते रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद कई जस्टिस ने पॉलिटिकल पार्टी भी जॉइन की है। इसी सिलसिले में हाल में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का नाम भी जुड़ गया। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस के पद से इस्तीफा देकर गंगोपाध्याय ने पिछले दिनों भाजपा जॉइन की। उसके बाद इस मसले पर एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पब्लिक रैली में बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में जनता मूल्यांकन करेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और ममता सरकार के बीच पहले भी कई बार तनातनी हो चुकी है। जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसलों को लेकर राज्य की टीएमसी सरकार कई बार असहज होती रही और सवाल उठाते हुए उन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देती रही है। हाल के सालों में जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले काफी चर्चित रहे हैं। कुछ अहम फैसलों पर एक नजर डाल लेना ठीक रहेगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में अनियमितता के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच ने सीबीआई और ईडी से जांच करवाने के आदेश दिए थे। इस मामले में ईडी ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नियुक्ति के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच ने अप्रैल 2023 में सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसी साल मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कैटिगरी में एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट जारी करने में हुई कथित अनियमितता मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी थी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने डबल बेंच के खिलाफ टिप्पणी की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसी दौरान अपने पद से इस्तीफा दिया और भाजपा जॉइन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस फजल 18 सितंबर 1951 को रिटायर हुए और उन्हें 7 जून 1952 को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीबी 1997 में तामिलनाडु की राज्यपाल बनी थीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र 90 के दशक की शुरुआत में रिटायर हुए थे। बाद में उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया और वह 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गए। चार साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायरमेंट के बाद बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे। उन्हें भाजपा सरकार ने मनोनीत किया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल ए नजीर को फरवरी में आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन, लॉ कमिशन का चेयरमैन और नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया जाता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या जजों को रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पद नहीं लेना चाहिए या फिर राजनीति को जॉइन नहीं करना चाहिए? इस बारे में जानकारों के अपने-अपने तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आरएम लोढा ने जज रहते हुए कहा था कि दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। वैसे तो उनका मत है कि जजों को राजनीतिक पद लेना ही नहीं चाहिए लेकिन अगर पद लेना भी है तो दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए।

सीएए पर भ्रम फैलाने की राजनीति करने में क्यों जुटा हुआ है विपक्ष?

सुरेश हिंदुस्तानी

भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक गुणा भाग का खेल प्रारंभ हो गया है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इस मामले में पूर्व नियोजित राजनीति ही कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार की ओर से बार बार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने वाला है, यह किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं करेगा। इसके विपरीत केंद्र सरकार के प्रत्येक कदम का विरोध करने वाले राजनीतिक दल इसे भारतीय मुसलमानों के विरोध में उठाया गया कदम बताने का भ्रम पैदा करने वाला रवैया बता रहे हैं। यहां एक बात यह भी स्पष्ट करने वाली है कि इस अधिनियम में भारत के मुसलमान कहीं हैं ही नहीं, फिर क्यों इस अधिनियम में मनमाफिक निहितार्थ तलाश करने की राजनीति की जा रही है? क्या इस प्रकार की राजनीति देश को मजबूत बना सकती है, यकीनन नहीं। क्योंकि जिस देश में कुतर्क की राजनीति की जाती है, वहां भ्रम का वातावरण ही निर्मित होगा। देश के राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह स्वच्छ और रचनात्मक राजनीति करके देश को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वह अपने एजेंडे से अलग कुछ भी नहीं कर रही है, नागरिकता का मुद्दा उसके लिए पहले से ही प्राथमिकता में रहा है। इतना ही नहीं अभी तक भाजपा नीत केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उन सभी को लेकर ही वह जनता के पास गई और भाजपा को ऐसा करने के लिए ही समर्थन मिला।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत यह भी स्पष्ट है कि इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समाज को ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है, इसके विपरीत इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। वे हिन्दू सहित अन्य गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी प्रताड़ना के कारण ही वे अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन प्रताड़ित लोगों के लिए किसी भी मुस्लिम देश में शरण नहीं मिलती। इसी कारण से भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। जबकि इन देशों में मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं किया जाता। इसके विपरीत भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने

वाले नेता इसका गलत अर्थ निकालकर भारतीय मुसलमानों को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। जबकि इस बात को यह भी भली भांति जानते हैं कि इस कानून से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला ही नहीं है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दुनिया में मुसलमानों को शरण देने वाले कई देश हैं, जबकि प्रताड़ित समाज को शरण देने के कोई भी मुस्लिम देश तैयार नहीं। इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय प्रथम दृष्टया उचित ही है।

वर्तमान में शरणार्थी और घुसपैठियों का अंतर समझने की बहुत आवश्यकता है। शरण वही मांगता है जो मजबूर हो गया हो और घुसपैठ करने वाला व्यक्ति एक उद्देश्य को लेकर चलता है। आज देश के लगभग आठ राज्य ऐसे हैं जहां घुसपैठ करने वाले नागरिक भारत में रह रहे हैं। इतना ही नहीं इनको भारत में राजनीतिक संरक्षण भी आसानी से मिल जाता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में खड़ी होती दिखाई देती हैं। यह केवल वोट की खातिर ही किया जा रहा है और यही तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। लेकिन सवाल यह आता है कि जब ये घुसपैठ करने वाले व्यक्ति अपने देश के प्रति वफादार नहीं हुए तो भारत के वफादार कैसे हो सकते हैं? इसलिए शरणार्थियों के लिए तो जगह हो सकती है, लेकिन घुसपैठियों को पनाह देना बहुत बड़े खतरे को आमंत्रण देने के समान ही कहा जाएगा।

वास्तविकता यह है ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह विरोध देश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है कि विपक्षी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए देश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास करने लगे हैं। मोदी का विरोध करते करते जाने अनजाने में देश का विरोध करने लगते हैं। एक समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह स्पष्ट तौर पर अभिव्यक्त किया कि कांग्रेस के नेता हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। कांग्रेस को आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात पर मंथन करना चाहिए था, लेकिन मंथन करना तो दूर उनको पार्टी से बाहर कर दिया। इसी प्रकार विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी गाहे बगाहे सनातन के विरोध में अप्रिय बयान देते रहे हैं। यह भी एक प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति ही कही जाएगी। ऐसी राजनीति भारत को भारत से अलग करने वाली है। यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि सनातन धर्म के बारे में गलत और विवादित बयान देने वालों के विरोध में कांग्रेस सहित अन्य दलों ने कोई बयान नहीं दिया। यह एक प्रकार से उनको समर्थन देना ही कहा जाएगा।

भारत की राजनीति के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि सरकार के निर्णय का बिना किसी नीति या सिद्धांत के विरोध किया जाए। ऐसा पहले भी होता रहा है। हम जानते हैं कि राफेल मामले में भी ऐसा ही विरोध हुआ और इस मामले में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को भी लिया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के राजनीतिज्ञ संभवतः यह भूल जाते हैं कि भारत की जनता चाहती क्या है? हम यह भी जानते हैं कि भारत की जनता राम से सीधा जुड़ाव रखती है। इसलिए यह कहा जा सकता है विपक्ष जनता के मनोभाव को समझने में अभी तक असफल ही रहा है। इसी प्रकार सीएए का मामला भी है। विपक्ष का यह कहना किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता कि यह मुसलमानों के विरोध में है। इसके प्रावधान के तहत ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी को नागरिकता नहीं दी जाएगी या किसी की नागरिकता छीनी जाएगी। जो बातें की जा रही हैं, वे केवल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। हां, इस कानून के तहत विदेशी मुसलमानों को नागरिकता नहीं दिए जाने की परिकल्पना निहित है, परंतु इसमें भारतीय मुसलमान का कहीं कोई परिलक्षण नहीं है। इसलिए विपक्ष केवल भ्रमित करने की ही राजनीति कर रहा है। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए।

संघ ने लिया राष्ट्रीय पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प

कृष्णमोहन झा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की परंपरागत त्रिवार्षिक बैठक गत दिनों नागपुर में संपन्न हुई। इस बैठक की समाप्ति के पश्चात् आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जब राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संघ का दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे थे तब उसमें असहमति की कोई गुंजाइश नहीं थी। कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कोई भटकाव नहीं,हर मुद्दे पर एक दम साफ़ सुथरा नजरिया। राष्ट्र हित और समाज हित से जुड़े हर मुद्दे पर संघ का यही स्पष्ट किंतु संतुलित दृष्टिकोण उसकी सबसे बड़ी पहचान रहा है।संघ न तो कभी अपनी दिशा बदलता है और न ही अपना दृष्टिकोण बदलता है।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत दिनों संपन्न त्रिवार्षिक बैठक में भी यही संदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि संघ की इस बैठक के मात्र दो माह पूर्व ही अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में राम लला की प्राण-प्रतिष्ठा का अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे और उस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके विद्वतापूर्ण व्याख्यान ने भी समारोह में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मोहन भागवत ने अपने उस व्याख्यान में जो सारगर्भित विचार व्यक्त किए थे वे संघ की त्रिवार्षिक बैठक में पारित प्रस्ताव में भी प्रतिध्वनित हुए हैं जिसमें इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि देश में हर तरह के परस्पर वैमनस्य और भेदभाव को समाप्त कर समरसता युक्त पुरुषार्थी समाज का निर्माण ही भगवान राम की सच्ची आराधना है ।

संघ की बैठक में पारित इस प्रस्ताव में अयोध्या में कहा गया है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण

हेतु पांच शताब्दियों के सतत संघर्ष और बलिदान तथा पूज्य संतों और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं समाज के विभिन्न घटकों के सामूहिक संकल्प के परिणामस्वरूप संघर्ष काल के दीर्घ अध्याय के सुखद समाधान हुआ। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने राममंदिर आंदोलन में प्राण अर्पण करने वाली हुतात्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आंदोलन में योगदान देने समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रस्ताव में कहा गया है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण से भारत में श्री राम के आदर्शों के अनुरूप समरस और सुगठित राष्ट्रजीवन खड़ा करने का वातावरण बना है।यह भारत पुनरुत्थान के गौरवशाली अध्याय के प्रारंभ का संकेत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन हमें सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज व राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की त्रिवार्षिक बैठक में लगातार दूसरी बार सरकार्यवाह निर्वाचित दत्तात्रेय होसबोले ने बैठक के समापन पर आमंत्रित पत्रकार वार्ता में कहा कि रामलला की अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घटना से समाज की सक्रिय भागीदारी का अनुभव सबने किया है। उन्होंने सामाजिक समरसता संघ की रणनीति का हिस्सा नहीं अपितु अटूट निष्ठा का विषय है।समाज की सज्जन शक्तियों के एकत्रीकरण और सभी के सामूहिक प्रयास से संभव होगा। संघ ने सभी को जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। सरकार्यवाह ने कहा कि संघ जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव सारे समाज पर दिखाई दे रहा है। संपूर्ण समाज को संगठित करने का स्वप्न साकार करने के लिए संघ कृतसंकल्प है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक समरसता के अभियान में संपूर्ण समाज की सहभागिता आवश्यक है।

दत्तात्रेय होसबोले ने चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व निरूपित करते हुए कहा कि संघ आगामी लोकसभा चुनावों में 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से जनजागरण अभियान चलायेगा। संघ के कार्यकर्ता बिखराव, अलगाव और वैमनस्य के प्रति सचेत रहने के लिए लोगों को जागृत करेंगे । उन्होंने इलेक्टोरल बांड को नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा पर आधारित प्रयोग बताते हुए कहा कि समय ही बताएगा यह कितना कारगर और फायदेमंद रहा। सरकार्यवाह ने कहा कि संघ हमेशा ही अल्पसंख्यकवाद की राजनीति का विरोधी रहा है। द्वितीय सरसंघचालक चालक गुरुजी से लेकर अभी तक सभी सरसंघचालकों ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के नेताओं से संवाद के द्वारा समन्वय बनाने का काम किया है। दत्तात्रेय होसबोले ने संदेशखाली और मणिपुर की घटनाओं को पीड़ा दायक बताया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 'फरसा' फिर से तैयार है

डॉ. ऋतु दुबे तिवारी

उत्तर प्रदेश को देश की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ की सियासत का सीधा असर केंद्र में देखने को मिलता है। गौरतलाब बात ये है कि देश को प्रभावित करने वाली उत्तर प्रदेश कि राजनीति में में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भले ही तकरीबन 12 फीसदी है लेकिन यह वर्ग प्रदेश की राजनीति को जबरदस्त प्रभावित करने की क्षमता रखता है। विधानसभा में करीब 115 सीटें ऐसी हैं, जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। आश्चर्यजनक बात ये रही कि ऐसे समय जब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है उस समय भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के मिज़ाज और समीकरण पर कोई बात नहीं हो रही थी। एक तरफ जहाँ भाजपा और इंडी गठबंधन दोनों में ओबीसी वोट की लड़ाई दिख रही थी तो दूसरी तरफ मायावती डीएम यानी दलित मुस्लिम समीकरण के भरोसे ही हैं। ऐसा उस राज्य में हो रहा है जहां 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं और 2022 के विधान सभा चुनाव में 52 ब्राह्मण विधायक बने थे। देखा जाए तो मंडल कमीशन के बाद से यूपी में दलित-ओबीसी राजनीति ने जोर पकड़ा और उसके बाद से अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन पाया लेकिन मतदाता के तौर पर इस जाति ने 90 के दशक के दौरान शुरुआती झटकों से उबरते हुए पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है। यही कारण है कि मनुवाद का सीधा विरोध करने और मंडल कमीशन के बाद बदले सियासी माहौल में सत्ता पर काबिज होने वाली सपा और बसपा भी बाद में ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने की रणनीति बनाने लगे। ब्राह्मण राजनीति का शोर नेपथ्य में जा ही रहा था कि इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने एक बार फिर ब्राह्मण स्वाभिमान और सम्मान को चर्चाओं में ला दिया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माला पहनाते हुए उन्होंने एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनता की आस्था का सम्मान करते हुए भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए सरकार ने वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। सियासत में कम शब्दों में संदेश कह देने की कला महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए जो इसमें माहिर है वह राजनीति के दांव पेंच में भी माहिर माना जाता है। ब्राह्मण स्वाभिमान के मुद्दे पर जितिन प्रसाद पिछले कुछ सालों में बेहद मुखर रहे, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए संगठन बनाया और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर ब्राह्मणों को एकजुट करने का अभियान चलाया। जितिन प्रसाद जब भाजपा में आए तब भी ये बात उठी थी कि जिस प्रकार ब्राह्मणों की नाराजगी को जितिन प्रसाद ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था वो उनके भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक रुप से भाजपा के पक्ष में हो गई है। जितिन आज जिस कुर्सी पर हैं उस पर कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और शिवपाल सिंह यादव जैसे दिग्गज रहे हैं। दोनों अपने अपने दलों में तो मजबूत रहे ही साथ ही अपनी जाति के लोगों के बीच नायक वाली छवि के साथ रहे और अब शायद जितिन भी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के बीच लगातार जाकर खुद को उसी नायक के रुप में स्थापित कर रहे हैं।

जानिए वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के बीज का अंतर, क्या इन दोनों में कोई संबंध भी है?

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों की ही अपना एक विशेष महत्व और नियम हैं। जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति कई तरह की समस्याओं से बच सकता है। साथ ही दोनों शास्त्रों में जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। लेकिन क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के बीच का अंतर।

वास्तु शास्त्र क्या है?

वास्तु शास्त्र हिंदू प्रणाली में सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। वास्तु शास्त्र घर, भवन अथवा मन्दिर निर्माण करने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। जिसे अंग्रेजी में हम आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। वास्तु शास्त्र यह भी बताता है कि जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उन्हें किस प्रकार रखा जाए। वस्तु शब्द से ही वास्तु का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी भवन या घर के निर्माण और डिजाइन में वास्तु के सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है।

जानें ज्योतिष शास्त्र का अर्थ

सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ग्रह, नक्षत्र आदि के स्वरूप, संचार, परिभ्रमण काल, ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का निरूपण एवं शुभ और अशुभ फलों का पता लगाया जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पता किया जा सकता है। साथ ही यह भी यह भी पती लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन-कौन से अवरोध उसकी राह में रुकावट डाल सकते हैं। दरअसल इसका संबंध भी विज्ञान से ही है।

वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में अंतर?

ज्योतिष एक वेदांग है, तो वहीं वास्तु शास्त्र अथर्ववेद के एक उपवेद स्थापत्य वेद पर आधारित है। ज्योतिष में जहां प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति की कुंडली के जरिये अध्ययन किया जाता है, तो वहीं वास्तु में भी भवन की संरचना का व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के बीच मुख्य अंतर यह है कि ज्योतिष खगोलीय पिंडों की व्याख्या और मानव पर उनके प्रभाव से संबंधित है, जबकि वास्तु शास्त्र, संतुलन और सद्भाव लाने के लिए इमारतों और घरों के डिजाइन और निर्माण पर केंद्रित है।

वास्तु और ज्योतिष के बीच सम्बन्ध

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही प्राचीनकाल में विकसित हुए विज्ञान हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि दोनों के बीच में एक गहरा सम्बन्ध भी हैं। असल में 'वास्तु शास्त्र' ज्योतिष शास्त्र का ही एक विकसित भाग है। वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही मानव पर पड़ने वाले सृष्टि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।

ग्रहों का घर के वास्तु पर कितना असर, किस हिस्से में कौन सी चीज रखना शुभ

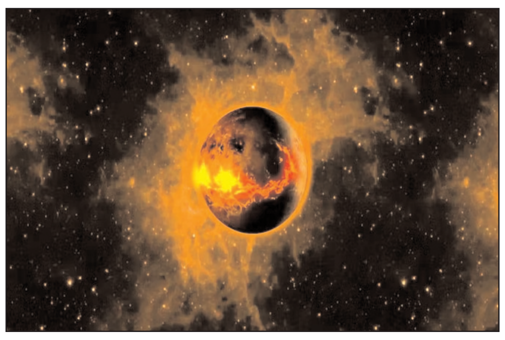

किसी भी वास्तु में नौ ग्रहों का आधिपत्य होता है एवं वास्तु में इनका स्थान निश्चित कोण पर होता है। इसी प्रकार प्रत्येक दिशा के देवता भी अलग-अलग होते हैं। घर में इनके संतुलित होने पर सुख-समृद्धि रहती है वहीं, इनके स्वभाव के विपरीत निर्माण करने पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे अनेकों प्रकार की परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी नौ ग्रहों का घर के वास्तु पर कैसा असर होता है।

सूर्य

पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य ग्रह एवं देवता इंद्र है। सूर्य स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और तेजस्व प्रदान करने वाला ग्रह है यदि घर की पूर्व दिशा दोषमुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले सदस्य महत्वकांक्षी, सत्वगुणों से युक्त और उनके चेहरे पर तेज होता है। ऐसे में भवन स्वामी को खूब मान-सम्मान मिलता है। इसलिए वास्तु में पूर्व दिशा को खुला छोड़ने की सलाह दी जाती है ताकि अंनत गुणधर्म वाली सूर्य की रश्मियां भवन में प्रवेश कर सकें। कभी भी इस दिशा को भारी व बंद नहीं करें।

शुक्र

शुक्र आग्नेय कोण के अधिपति ग्रह एवं इस दिशा के देवता अग्निदेव हैं। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जिस भवन में दक्षिण-पूर्व या आग्नेय कोण शुभगुणों से युक्त और दोष रहित होता है ऐसे वास्तु की आंतरिक ऊर्जा स्वस्थ्य और शुक्र के गुणधर्म वाली होती है। इस दिशा में रसोई, बिजली के सामान एवं विद्युत केंद्र होना वास्तु के अनुसार शुभ माने गए हैं।

मंगल

दक्षिण दिशा मंगल ग्रह के अधीन होती है एवं इस दिशा के देवता यम हैं। मंगल ग्रह समस्त प्रकार का साहस एवं धन लाभ प्रदान करने वाला होता है। मंगल ग्रह निडर, साहसी और दिलेर होता है और यह युद्ध, लड़ाई, क्रोध का अधिपति भी है। दक्षिणदिशा विधि, न्याय, मुकदमेबाजी, आराम, जीवन और मृत्यु से संबंधित है। इसलिए इस दिशा में शयन कक्ष तथा भण्डार गृह रखना चाहिए।

राहु

दक्षिण पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण का स्वामी राहु ग्रह है एवं इस दिशा की देवी आसुरी शक्ति वाली हैं। इस दिशा में तमस तत्व सर्वाधिक होता है इसलिए वास्तु में इस दिशा को सबसे अधिक भारी रखना शुभ होता है। घर में भूलकर भी इस दिशा को हल्की एवं खुली नहीं रखें। इस दिशा में बैडरूम, ऑफिस, बाथरूम या स्टोर रूम बनाना लाभदायक रहता है।

शनि

पश्चिम दिशा लाभ एवं प्रसन्नता की दिशा है। इस दिशा के ग्रह शनि एवं देवता वरुण देव है। शनि ग्रह भाग्य, कर्म, यश तथा पौरुष संबंधी कार्यों का कारक होता है। इस दिशा को हमेशा स्वस्थ्य रखना चाहिए। इस दिशा में ड्राइंगरूम, बेडरूम, पुस्तकालय होना शुभ होता है।

चन्द्रमा

वायव्य दिशा का स्वामी चन्द्रमा है। यह शांत चित्त एवं भाग्य का अधिपति ग्रह है। यह मन, चित्तवृत्ति, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, संपत्ति व माता का कारक है। वहीं वास्तु में वायव्य कोण वायुदेव का स्थान है। वायुदेव हमें शक्ति, प्राण, स्वास्थ्य प्रदान करते है। सामाजिक जीवन एवं व्यापार पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इस दिशा में भोजनकक्ष,अतिथि गृह, विवाह योग्य कन्याओं का कमरा एवं बिना टॉयलेट के बाथरूम होना शुभ होता है।

बुध

यह ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी एवं इस दिशा के देवता कुबेरदेव होते हैं। बुध वाक्चातुर्य एवं विद्धता का प्रतिनिधि ग्रह है। जिस घर में उत्तर दिशा शुभ होती है वहां के लोग अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान, लेखन एवं कविता में रूचि रखने वाले होते हैं। बुध सम्पन्नता और करियर का प्रतिनिधि ग्रह है इसलिए इस दिशा में अध्ययन कक्ष, तिजोरी और पुस्तकालय शुभ माने गए हैं।

गुरु

यह उत्तर-पूर्व या ईशान कोण का स्वामी ग्रह है एवं विष्णुदेव इस दिशा के देवता हैं । गुरु, ईश्वरीय तेज एवं आध्यात्मिक वृत्ति का प्रदाता ग्रह है। बौद्धिक विकास एवं बौद्धिक शांति के लिए तथा ईश्वर की कृपा पाने के लिए यह दिशा स्वस्थ्य रखनी चाहिए। इस दिशा में पूजा स्थल एवं योग कक्ष बनाना अत्यंत शुभकारी है।

रसोईघर में भूलकर भी उल्टे नहीं रखने चाहिए ये दो बर्तन

घर में हो सकता है दरिद्रता का वासह्य

वास्तु शास्त्र में कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया गया है। यदि इन बातों को अपनाया जाए, तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। वास्तु जानकारों के मुताबिक वास्तुशास्त्र में रसोईघर यानी किचन के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है। जिसे यदि जाने-अंजाने नजरअंदाज कर दिया जाए, तो व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में बताई गई बातों का पालन कर कुछ समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

वास्तुशास्त्र के अनुसार, किचन को लेकर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग किचन में कुछ बर्तनों को उल्टा रख देते हैं। ऐसे में बर्तनों को उल्टा रखना कंगाली का कारण बन सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि रसोई में किन दो बर्तनों को उल्टा रखने से बचना चाहिए।

तवा न रखें उल्टा

वास्तु शास्त्र में किचन संबंधी ऐसे नियम बताए गए हैं, जो व्यक्ति को आने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। किचन में रोटी बनाने के बाद कभी भी तवा को उल्टा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने पर व्यक्ति को आर्थिक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप पर कर्ज बढ़ सकता है और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है।

कड़ाही न रखें उल्टा

किचन में तवे के अलावा कड़ाही को भी कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप अंजाने में भी कड़ाही को उल्टा रखते हैं, तो व्यक्ति को घर में नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है।

झूठे बर्तन

वास्तु शास्त्र के मुताबिक कभी भी किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। वहीं तवा और कड़ाही का इस्तेमाल करने के बाद इसको हमेशा धोकर रखना चाहिए। क्योंकि तवा और कड़ाही को गंदा छोड़ने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और दरिद्रता का वास होता है।

किस दिशा में रखें बर्तन

किचन में यदि तांबे, कांसे, स्टील और पीतल के बर्तन हैं। ऐसे में किचन में इन बर्तनों को हमेशा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा बर्तन रखने के लिए उत्तम मानी जाती है।

लठ्ठमार होली-लड्डुओं की मिठास से शुरू हुई रंगों वाली होली

विश्व प्रसिद्ध लठामार होली से एक दिन पूर्व होने वाली लड्डू होली को देखने के लिए सुबह से ही बरसाना की ओर भक्तों का रेला चल पड़ा। बरसाना की ओर जाने वाले हर मार्ग पर सिर्फ भक्तों का रेला राधारानी के जयकारे लगाते नजर आ रहा था। धीर-धीरे लाडिलीजी मंदिर में भक्तों की भीड़ से अटने लगा। दोपहर में राजभोग आरती से पहले चप्पा-चप्पा भीड़ से अट चुका था। हाल ये था कि श्रीजी मंदिर की सीढ़ियों पर भी पांव रखने तक की जगह थी। श्रद्धालु एक-दूसरे को अबीर-गुलाल से सराबोर कर रहे थे। दोपहर बाद श्रद्धालु मंदिर में सफेद छतरी के सामने छौटी सिंह पौर पर ही रुकने लगे। हर किसी को इंतजार लड्डू होली का था। शाम को चार बजे मंदिर खुलने से सफेद छतरी की छौटी सिंह पौर पर भी भीड़ का दबाव बढ़ गया। भक्ति भाव में विभोर श्रद्धालु धक्का-मुक्की की परवाह किए बगैर ही श्रद्धालुओं ने लड्डू होली शुरु होने से पहले ही अपने साथ लाए लड्डूओं को लुटना शुरु कर दिया। इसके बाद सायं पांच बजे लड्डू होली की शुरुआत हुई।

मंदिर के पुजारी नृत्य गोपाल गोस्वामी, मधु मंगल पांडा बनकर कर समाज गायन पर नृत्य करने लगे। मंदिर चौक में इस नृत्य को देख भक्त भी खुद को नहीं रोक सके, जो जहां था वहीं थिरकता नजर आया। नृत्य के बीच ही पांडे को भक्तों ने लड्डू भोग को दिए तो पांडे ने रंग-गुलाल के बदरों के मध्य नंदगांव कौ पांडो ब्रज बरसाने आयौ, भरि होरी के बीच सजन समध्याने धायौ.... की धमार पर नाचते हुआ लड्डू लुटाने शुरु कर दिए। इन लड्डूओं को लूटने के लिए हर कोई लालायित रहा। श्रद्धालु एक-दूसरे को धकियाने में भी पीछे नहीं रहे। देश के विभिन्न प्रान्तों से आये लाखों भक्त ऊंच नीच, गरीब, अमीर के भेदभाव को भूलकर लड्डू रूपी प्रसादी लूटने में जुटे रहे।

होली की दूसरी चौपाई निकाली

लठामार होली की पूर्व संध्या पर लाड़लीजी महल से सुदामा चौक में बाजार फूल गली होते हुए रंगीली गली स्थित रंगेश्वर महादेव तक होली की द्वितीय चौपाई निकाली गई। इस चौपाई में भी भक्तों ने अबीर-गुलाल की जमकर वर्षा की। हर कोई होली की मस्ती में डूबा नजर आया। होली की चौपाई पर जगह-जगह पुष्प वर्षा भी हुई।

नई व्यवस्था के चलते खाली रही रंगीली गली

श्रद्धालुओं को राधा रानी के दर्शन मिल सके इसके लिए नया रूट प्लान बनाया गया। श्रद्धालुओं को तो राधारानी के दर्शन मिल गए, लेकिन चार गालियां रंगीली गली, फूल गली, प्रेम गली, टांटियां मोहल्ला, चेना का थोक के लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत उठानी पड़ी। आवश्यक कार्य को निकले स्थानीय लोगों की बैरियर पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से जद्दोहद तक हुई।

लठामार का न्योता मिलते ही नंदगांव में मना जश्न

लठामार से पूर्व राधा रानी महल से नंद महल में फाग आमंत्रण लेकर पहुंची सखी। होली खेलने का पत्र मिलते ही सभी नर नारी झूम उठे और नंदमहल में जमकर अबीर गुलाल के मध्य नृत्य हुआ। रविवार को सुबह से ही नंदगांव में भारी उल्लास था। कान्हा और उनके सखाओं को होली का न्योता मिलने का बेसब्री से इंतजार था। नंदभवन में सखियों को नचाने के लिए सुंदर स्टेज सजाया गया। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कृष्ण बलराम को आकर्षक पोशाकें पहनाई गईं। उधर, बरसाना से प्रात दस बजे राधा सखी, गोपाल सखी राधा रानी मंदिर से इत्र, फुलेल, लड्डू, पान बीड़ा के साथ रंग गुलाल की हंडिया के साथ मंदिर से बैंडबाजों व ढोल-बजाते हुए रंगीली गली होते हुए निकलीं। फाग आमंत्रण को लेकर दोनों सखी नंद भवन में पहुंचीं। सखियों को देख मंदिर परिसर में हल्ला मच गया कि बरसाना से न्योता आ गया है। उन्होंने बरसाना से लाए प्रसाद मंदिर सेवायतों को दिया। प्रसाद का मंदिर में नंदबाबा व यशोदा मैया के साथ कृष्ण-बलराम का भोग लगाया।

रंगभरी एकादशी के दिन क्यों होती है विष्णुजी के साथ शिव-गौरी की पूजा?

हिंदू धर्म में हर साल शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णुजी की पूजा-उपासना का बड़ा महत्व है, लेकिन फाल्गुन माह में एकमात्र ऐसी एकादशी है, जिस दिन विष्णुजी के साथ मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा-आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रंगभरी एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं रंगभरी एकादशी की सही डेट, मुहूर्त और इस दिन शिव-गौरी के पूजन का महत्व...

कब है रंगभरी एकादशी ?

आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त- हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुरुआत दोपहर को 12 बजकर 21 मिनट पर होगी और अगले दिन यानी 21 मार्च को 2 बजकर 22 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए उदयातिथि के अनुसार, 20 मार्च को आमलकी यानी रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी।

पारण की टाइमिंग- 21 मार्च को दोपहर 1 बजकर 7 मिनट से लेकर 3 बजकर 32 मिनट तक आमलकी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है।

रंगभरी एकादशी पर शिव-गौरी के पूजन का महत्व- रंगभरी एकादशी एकमात्र ऐसी एकादशी है, जिसमें विष्णुजी के साथ माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन का बड़ा महत्व है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, रंगभरी एकादशी के दिन पहली बार भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर उन्हें काशी लेकर आए थे। इसलिए फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर विष्णुजी के साथ शिव-गौरी की भी पूजा-उपासना की जाती है। इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने रंग,अबीर, गुलाल और रंग-बिरंगे फूलों से माता पार्वती का स्वागत किया था। इसलिए इसे रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री पशुपति का इस्तीफा स्वीकार किया

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रीजीजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भाजपा पर बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत में अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को शामिल नहीं करके उसके साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार, ''राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर पशुपति कुमार पारस का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।'' राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर किरेन रीजीजू को उनके मौजूदा विभाग के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कामकाज भी देखने का निर्देश दिया है।

तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल सुंदरराजन भाजपा में शामिल

हैदराबाद। तेलंगाना की राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, तमिलिसाई सौंदरराजन बुधवार को चेन्नई में तमिलनाडु पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गईं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। सुंदरराजन का इस्तीफा तब सार्वजनिक किया गया जब पीएम मोदी राज्य के जगतियाल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तमिलिसाई ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा और एक प्रति मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजी। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के बाद मोदी रविवार से तेलंगाना राजभवन में ठहरे थे। चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए, तमिलिसाई ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सार्वजनिक सेवा लेने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैंने अपनी इच्छा अपनी पार्टी को भी बता दी है।

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नईदिल्ली। ईडी फिलहाल तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को दिल्ली नहीं बुला सकती है। कोयला तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि, ईडी डायमंड हार्बर के तृणमूल सांसद के खिलाफ कोई 'सख्त कार्रवाई' नहीं कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। इस संदर्भ में अभिषेक के वकील संजय बसु ने कहा, वादी एक सांसद हैं। वह आगामी लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा नरूला बंद्योपाध्याय जांच एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। अदालत में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले को स्वीकार किया।साथ ही उन्होंने कहा, मार्च 2022 के बाद ईडी ने इस मामले में अभिषेक को समन नहीं किया। उसी साल सितंबर के बाद कोयला तस्करी मामले में भी रुजिरा को समन नहीं किया गया था।

तौकीर रजा को 27 से पहले सरेंडर करने कोर्ट का आदेश

लखनऊ। मौलाना तौकीर रजा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरेंडर के लिए 27 मार्च की तारीख भी तय कर दी है। यानी 27 मार्च से पहले तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। हालांकि सरेंडर के बाद जमानत की अर्जी ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने की उन्हें छूट हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तौकीर रजा की अर्जी पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश भी दिए हैं। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड बताया था। उनके खिलाफ लगातार दो तारीख से गैर जमानती वारंट जारी हो रहा है। इस बार तौकीर को गिरफ्तार कर पेश करने की जिम्मेदारी कोर्ट ने सीधे एसएसपी सुशील घुले को दी थी। मौलाना तौकीर रजा खान सख्त लहजे में कहते नजर आए कि हमें किसी भी हरकत पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर न करें। हमने हाथों में चूड़ियां भी नहीं पहनी हैं।

झारखंड के भाजपा विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल

रांची। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के भारतीय जनता पार्टी विधायक जय प्रकाश भाई पटेल बुधवार को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए. पक्ष बदलने के बाद, उन्होंने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का भी वादा किया। पटेल को कांग्रेस में शामिल करने का कार्यक्रम पार्टी मुख्यालय में एआईसीसी के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर, झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा सहित प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में हुआ। हज़ारीबाग़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मांडू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पटेल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विधायक के रूप में कार्य कर चुके हैं। पटेल ने कहा कि वह अपने पिता और पूर्व सांसद टेक लाल महतो के झारखंड के सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह एनडीए में अपने पिता की विचारधारा को खोजने में असमर्थ हैं।

स्टार्टअप महाकुंभ में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विकसित देश बनने के लिए रोडमैप बना रहा है भारत

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, राजनीति में तो ये बहुत ज्यादा होता है और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में और उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं, एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कई लोग स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, खासकर राजनीति में, कभी-कभी कई बार...आपमें और उनमें अंतर यह है कि आप प्रयोगात्मक हैं। एक लॉन्च की विफलता के बाद आप नए विचारों को आजमाते हैं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और साफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्ट-अप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्ट-अप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए हैं। सही समय पर स्टार्ट-अप को लेकर काम शुरू किया।

मोदी ने कहा कि आज, ऊर्जा और जीवंतता अद्भुत है! स्टालों पर घूमते हुए और आपके आविष्कारों को देखते हुए, मैं यह महसूस कर सकता हूं कि भारत के भविष्य में कई यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सही समय पर सही फैसले लिये। उन्होंने कहा कि देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत प्रगतिशील विचारों को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। शैक्षणिक संस्थानों में इनक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया और उसकी बाल वाटिका के रूप में हमने अटल टिंकरिंग लैब शुरू की। उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस और यहां तक कि योग और आयुर्वेद के स्टार्टअप भी शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस के 50 से अधिक

सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष शटल लॉन्च करने लगे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने स्टार्टअप-20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। इसी भारत मंडपम में जी-20 के दिल्ली डिक्लियरेशन में पहली बार स्टार्टअप को न सिर्फ इनक्लूड किया गया, बल्कि उन्हें नेचुरल इंजिन ऑफ ग्रोथ भी माना गया।

मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं जो 12 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न हैं... हमारे स्टार्टअप ने 12,000 से अधिक पेटेंट पंजीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि इस अंतरिम बजट में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि एआई युवा नवप्रवर्तकों और वैश्विक निवेशकों के लिए कई रास्ते खोलता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहल युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोलती हैं।

मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं देश की महिलाएं : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस नेता ना तो हमारी परंपरा को जानते हैं और न ही उसका सम्मान करते हैं। एक नीजी चैलन पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की महिलाएं पीएम मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हमारे देश में मातृशक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मां के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है और बहन के स्नेह से बड़ा कोई स्नेह नहीं हो सकता है। उन्होंने वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि वो क्या बाल रहे हैं। मोदी जी के साथ इस देश की नारी शक्ति चट्टान की तरह खड़ी है। नारी शक्ति ने ठाना है कि इस बार चुनाव में राहुल गांधी को शक्ति का परिचय जरूर कराना है।

विपक्ष पर वार करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की पॉलिसी ही है कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए, साउथ इंडिया और नार्थ इंडिया। लेकिन राहुल बाबा आप चिंता न करें, अब भाजपा इतनी ताकतवर है कि कांग्रेस दूसरी बार देश का विभाजन नहीं कर पाएगी। हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई कि सीएए से देश के अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है।

अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि ममता के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपये मिलते हैं, कांग्रेस के सांसद के घर से ×55 करोड़ रुपये मिलते हैं और ये कहते हैं कि कार्रवाई ही न हो। नोटों की गड्डियां भरने के लिए मेटाडोर लाने पड़ते हैं। देश की जनता को राहुल बाबा बता सकते हैं कि ये पैसा कहां जाने वाला था? उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। जो करप्शन करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, वो जेल के पीछे जाएगा।

लद्दाख को लेकर संवेदनशील नहीं सरकार : कांग्रेस अध्यक्ष

खरगे ने पीएम पर लगाया लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। खरगे ने कहा है कि मोदी सरकार ने चीन से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला और लद्दाख के लोगों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख की रक्षा और सीमाओं पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।

मोदी की चाइनीज गारंटी- खरगे

खरगे ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा है 'मोदी की चाइनीज गारंटी'। उन्होंने आगे लिखा है कि लद्दाख में आदिवासी समुदायों की सुरक्षा के लिए जनता का मजबूत समर्थन मिल रहा है। लद्दाख के लोगों के संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मोदी की गारंटी एक बड़ा धोखा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लद्दाख को लेकर संवेदनशील नहीं है। उनके अनुसार सरकार हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन कर के अपने 'क्रोनी दोस्तों' को फायदा पहुंचाना चाहती है। खरगे ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे बीस जवानों के शहीद होने के बाद भी पीएम मोदी की चीन को क्लीन चिट दे दी। इस वजह से हमारी सीमाओं पर चीन की विस्तारवादी सोच को बढ़ावा मिला है। कांग्रेस प्रमुख ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि एक तरफ, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है, दूसरी तरफ, लद्दाख के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने आगे कहा कि चीन ने देपसांग मैदान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जारी रखा है।

मोदी पर जयराम रमेश ने साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी चीन नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि चीन को क्लीन चिट देकर पीएम मोदी ने अपने हाथ बांध लिए हैं। जयराम रमेश के अनुसार चीनी आक्रमण के बाद प्रधानमंत्री कार्रवाई करने में विफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले चीन से आयात में भारत की 11 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। अब बीते कुछ वर्षों में यह हिस्सेदारी औसतम 15 प्रतिशत बढ़ गई है। जयराम रमेश ने यहां मालदीव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मालदीव ने हिंद महासागर में निगरानी रखने के लिए तुर्की निर्मित सैन्य ड्रोन भी तैनात किए हैं। अपने ही पड़ोस में चीन का हस्तक्षेप बढ़ रहा है और इस स्थिति में भारत की क्या कार्य योजना है?

आपको बता दें कि लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक उपवास पर हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की छठी अनुसूची को लागू किया जाए। वांगचुक ने लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटों की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की भी मांग की है। इस दिशा में केंद्र सरकार से बातचीत विफल रही और वांगचुक ने छह मार्च को अपना अनशन शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद उनके उपवास में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

खेल
प्रमुख समाचार

सीएसके और आरसीबी के बीच पहला मुकाबला कल

नईदिल्ली। आईपीएल 2024 का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। सीएके इस वक्त आईपीएल की सबसे सफल टीम है जबकि आरसीबी पिछले 16 सालों से खिताब के लिए तरस रही है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है।

चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत कप्तान एमएस धोनी हैं। धोनी को पता है कि किस खिलाड़ी को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सीएसके की ताकत उसकी बल्लेबाजी रही है। पिछले सीजन में भी टीम ने खिताब अपने नाम बल्लेबाजी के दम पर ही किया था। टीम के पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, जो कि एक और प्लस पॉइंट टीम के पास है। स्पिनर भी रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटनर और महेश थीक्षणा के रूप में दमदार हैं। वहीं टीम की कमजोरी की बात करें तो, टीम के बेहतरी गेंदबाज मथीशा पथिराना और मुशफिकुर रहीम चोटिल हैं। हालांकि, ये कमजोरी कुछ ही मैचों में नजर आएगी। जैसे ही ये खिलाड़ी फिट हो जाएंगे तो फिर गेंदबाजी भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा टीम के साथ समस्या ये है कि शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ताकत भी हमेशा से बल्लेबाजी रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी टॉप 5 या ज्यादा से ज्यादा टॉप 6 तक ही बल्लेबाजी नजर आती है। टीम के पास तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं, मोहम्मद सिराज, अल्जारी जोसेफ और आकाशदीप टीम के पास मौजूद हैं। वहीं टीम की कमजोरी बल्लेबाजी में गहराई और स्पिन विभाग है। अनुभवी कर्ण शर्मा के अलावा टीम के पास कोई स्पिनर नहीं है। हालांकि, इस बार कैमरोन ग्रीन भी अपनी गेंदबाजी का हुनर दिखाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 90 अंक चढ़कर बंद निफ्टी 22 हजार के नीचे

नईदिल्ली। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को देसी शेयर बाजार भारी उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 90 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 22 अंक की बढ़त दर्ज की गई। एक समय सेंसेक्स 728 अंक तक उछल गया था। व्यापक बाजारों में, बीएसई मिडकैप 0.05 प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक में 0.14 प्रतिशत की गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 89.64 अंक यानी 0.12 फीसदी की बढ़त के साथ 72,101.69 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 71,674.42 और 72,402.67 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 21.65 अंक यानी 0.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 21,839.10 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,710.20 और 21,930.90 के रेंज में कारोबार हुआ।

अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों को लगे पंख

नईदिल्ली। आज यानी 20 मार्च को 5 फीसदी की बढ़त पर हैं। बीएसई पर शेयर आज दिन के उच्चतम स्तर 23.83 रुपये पर पहुंच गए थे। बता दें, कंपनी के शेयरों में यह तेजी रिलायंस पावर के द्वारा बैंकों के कर्ज चुकता किए जाने की खबर के बाद आई है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने पिछले हफ्ते तीन बैंकों- आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक का कर्ज चुकाया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इसकी मूल कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ?2,100 करोड़ का बकाया निपटाने की दिशा में काम कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक वाणिज्यिक बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया, 'रिलायंस पावर का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त कंपनी बनना है।

एयरटेल की कंपनी के आईपीओ के लिए सेबी ने दी मंजूरी

नईदिल्ली। बाजार में जल्द ही एक और टेलीकॉम कंपनी की एंट्री होने वाली है। भारती एयरटेल की सब्सडियरी भारती हेक्साकॉम को आईपीओ के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। ओएफएस के तहत, टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 10 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। हेक्साकॉम के आईपीओ में कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा और यह पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) पर आधारित होगा। ओएफएस के जरिए कंपनी की इकलौती पब्लिक शेयरहोल्डर, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अपने 10 करोड़ शेयरों को बेचेगी। यानी की आईपीओ से मिलने वाली पूरी धनराशि कंपनी के पास न जाकर, टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के पास जाएगी। सेबी ने इसके आईपीओ आवदेन पर 11 मार्च को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया था।

जोमैटो का वेज फ्लीट की 'ग्रीन यूनिफॉर्म' का फैसला

नईदिल्ली। जोमैटो ने अपने प्योर वेज फ्लीट के डिलीवरी पर्सन के लिए रेड की जगह ग्रीन यूनिफॉर्म का फैसला वापस ले लिया है। घोषणा के एक दिन के भीतर ही जोमैटो ने इस फैसले को वापस ले लिया। दरअसर जोमैटो ने हाल ही में वेज खाना खाने वालों के लिए एक खास सेवा शुरु की थी। शाकाहारी खाने को तरजीह देने वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'प्योर वेज मोड' सर्विस का ऐलान किया था, जिसके तहत 100 फीसदी वेज खाना पसंद करने वालों के लिए प्योर वेज रेस्ट्रां से खाना डिलीवर किया जाएगा और वेज खाना डिलीवर करने के लिए जोमैटो में एक अलग से एक डिलीवरी पर्सन की शाखा बनेगी जिसे प्योर वेज फ्लीट का नाम दिया गया। कंपनी के संस्थापक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी थी।

भारतीय ज्यादा खरीद रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट

मधुरेंद्र सिन्हा

देश में लग्जरी सामानों की बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी है कि दुनियाभर में भारत की चर्चा है। साल 2023 में एक अभूतपूर्व घटना हुई कि कम कीमत वाले उत्पादों से कहीं ज्यादा प्रीमियम प्रॉडक्ट की बिक्री हुई। अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने 'समृद्ध भारत का उदय' नामक अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि महंगे उत्पाद बनाने वाली कंपनियां सामान्य किस्म के सामान बनाने वाली कंपनियों की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं।

कई प्रॉडक्ट के मामले में तो बढ़ोतरी 50 फीसदी से भी ज्यादा रही। इस अभूतपूर्व तेजी का क्या कारण हो सकता है? इस सवाल का जवाब अमीरों के बारे में लिखने वाली विदेशी पत्रिका फोर्ब्स ने दिया है। इसका बड़ा कारण यह है कि संभावित ग्राहकों की मानसिकता में जबरदस्त बदलाव हुआ है। भारत के तेज आर्थिक विकास ने एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया है, जिसके पास पैसा है और उसे खर्च का दिल भी है। यह कारोबारियों, उद्यमियों, मोटी सैलरी वाले एग्जीक्यूटिव, स्टार्ट-अप और धनाढ्य लोगों की दूसरी पीढ़ी है, जो प्रीमियम प्रॉडक्ट खरीदने से हिचकती नहीं है। यह मूलतः युवा वर्ग है, जो 30 से 40 साल उम्र का है और जिसकी महत्वाकांक्षाएं आकाश छू रही हैं। यह वैसा वर्ग है, जिसमें अपने सपनों को देखने के बजाय पूरा करने की चाहत है। इसका एक उदाहरण है कि दुनिया की सबसे स्टाइलिश कार लैंबोरिजिनी की बिक्री भारत में पिछले साल से बढ़ती जा रही है।

बचत शब्द इन ग्राहकों के शब्दकोश में नहीं है। यही वही कारण है कि महंगे मकानों की अचानक मांग बढ़ गयी है। मुंबई ही नहीं, गुड़गांव में भी पांच करोड़ से दस करोड़

रुपये के अपार्टमेंट की बिक्री बढ़ी है और बिल्डर ऐसे मकान बनाने में तेजी दिखा रहे हैं। महंगे स्मार्टफोन भी खूब बिक रहे हैं। पिछले दिनों तीन स्मार्टफोन कंपनियों ने सवा-सवा लाख रुपये कीमत वाले स्मार्टफोन लॉन्च किये, जिनकी बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। साल 2023 में 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाले स्मार्टफोन की बिक्री कम दाम वाले फोन से ज्यादा बढ़ी है। त्योहारों के पहले हफ्ते में डेढ़ लाख आई-फोन बिक गये थे, जो एक रिकॉर्ड है।

जिन लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण देखा-सुना होगा, उन्हें याद होगा कि वे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए अन्य कारणों के अलावा घरेलू खपत को भी श्रेय दे रही थीं। उनका कहना था कि घरेलू खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था भी ऊपर जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आधारित नहीं है और यहां जितनी खपत बढ़ती है, उतनी ही उसमें तेजी भी आती है क्योंकि उससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब देश में महंगे सामानों की बढ़ती बिक्री का ट्रेंड है, तो इससे अर्थव्यवस्था को यह लाभ होगा कि बड़े पैमाने पर धन का प्रवाह बाजार में होगा। यह पूंजी के रूप में कारोबार को बढ़ावा देगा। सामानों-कारों की बढ़ी हुई बिक्री से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। लेकिन सवाल फिर भी है कि कम दाम के सामानों के उत्पादन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो फिर उन पर असर पड़ेगा। इससे रोजगार में कमी आयेगी। जरूरी है कि एक संतुलन बना रहे। देश को इस समय रोजगार की जरूरत है, जो उत्पादन बढ़ने से ही मिलेगा। मांग में बढ़ोतरी तभी होगी, जब निचला तबका अधिक खरीद करेगा। प्रीमियम या लग्जरी उत्पादों की बिक्री बढ़ने का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह हो सकता है कि लग्जरी कारों के उत्पादन में वृद्धि से उन कंपनियों का लाभ बढ़े और उनकी पूंजी भी, जिसका उपयोग वे उत्पादन बढ़ाने में कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में महंगाई बढ़ी है, जिससे उत्पादों की मांग में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हो पायी है। सच तो यह है कि यह अभी तक पूर्व कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पायी है। उस समय जो खपत थी, वह अभी नहीं लौटी है। यह चिंता का विषय है।

लोकसभा निर्वाचन 2024-सेक्टर अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला

सेक्टर अधिकारी मतदान दल और आरओ के बीच कड़ीः कलेक्टर

सेक्टर अधिकारी निष्पक्षता से कार्य करें-एसपी

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में सेक्टर और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जहां सेक्टर अधिकारियों को मतदान दल और आरओ के बीच की कड़ी बताया। वहीं एसपी संतोष सिंह ने सेक्टर अधिकारियों से निष्पक्षता से कार्य करने को कहा।

प्रशिक्षण में शामिल हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सेक्टर अधिकारी गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। सेक्टर अधिकारी मतदान दल और रिटर्निंग अधिकारी के बीच कड़ी होते है। निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न होने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सेक्टर पुलिस अधिकारी कानून व्यवस्था, कहीं पर किसी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे।

लोकसभा निर्वाचन गर्मी के मौसम में होना है, ऐसे में सभी सेक्टर अधिकारी समय पूर्व बूथ का निरीक्षण करें और मूलभूत सुविधा व्यवस्थित करें। स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी में जाएं और वहां और किसी भी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन न हो रहा हो, इसका विशेष ध्यान रखें। बूथ में वेबकास्टिंग के कार्य को बेहतर तरीके से कराएं और सम्पूर्ण मतदान के बाद ईवीएम मशीन सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएं। सेजबहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्याप्त सुविधाएं रखी जाएगी।

एसपी संतोष सिंह ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता के साथ ड्यूटी करें। शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ कार्य करें। निर्वाचन कार्य के द्वारा आचार-व्यवहार बनाएं रखें। मतदान के पूर्व भी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

मास्टर ट्रेनर अजीत हंडेत ने सेक्टर अधिकारियों को बताया कि मतदान केंद्र में 100 मीटर तक प्रचार-प्रसार न हो, इसका चिन्हांकन करना होगा।

भाजपा कोरबा लोस प्रबंधन एवं कोर कमेटी की बैठक प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन की उपस्थिति में हुई संपन्न

जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कृत संकल्पित

बघेल के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति मिलीः नबीन

रायपुर। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रत्याशी डॉ सुश्री सरोज पांडेय ने कहा की कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा को 370 प्लस एवं एनडीए 400 पार का नारा दिया है। हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर उनके संकल्प को पूरा कर दिखाना है। मैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी तो प्रतीक मात्र हूं वास्तविकता में तो यहां का प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है।

बैठक में उपस्थित अपेक्षित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा की विधानसभा चुनाव के पहले देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना अधिक मुश्किल जान पड़ता था लेकिन छत्तीसगढ़ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम की और इसी का परिणाम था कि भूपेश बघेल के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति मिली है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के मेहनत के भरोसे मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से हम 11 की 11 सीट जीतकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन ने लोकसभा प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी के अन्य विषयों में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। लोकसभा प्रबंधन एवं कोर कमेटी की बैठक को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में हम कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए आत्मविश्वास की बदौलत लोकसभा की सभी सीटे जीतने का दावा कर रहे हैं। आज हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है, ऐतिहासिक उपलब्धियां है। अब हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए वोटर के पास जाए एवं उनसे समर्थन प्राप्त करें।

आज के बैठक में उपरोक्त अतिथियों के अलावा मुख्य रूप से बिलासपुर क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, कोरबा लोकसभा प्रभारी धरम लाल कौशिक, लोकसभा संयोजक एवं बैकुंठपुर विधायक भैया लाल राजवाड़े, लोकसभा सहसंयोजक मनोज शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्रम व उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, भरतपुर सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, मरवाही विधायक श्री प्रणव मरपच्ची, ननकी राम कंवर, श्रामदयाल उइके, गोपाल साहू, प्रबल प्रताप जूदेव, कोरबा जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह, कोरिया जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, एमसीबी जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी, जीपीएम जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया राठौर सहित सभी विधानसभाओं के संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी, लोकसभा में निवासरत प्रदेश के कार्य समिति सदस्य, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रबंधकारिणी व कोर कमेटी के सदस्य सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

बस्तर सीट पर पूर्व मंत्री लखमा के बेटे और पीसीसी चीफ की दावेदारी से फंस गया पेंच !

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है. अब तक 5 सीटों पर नाम फाइनल नहीं किया जा सका है. इस बीच जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा अपने बेटे हरीश लखमा के लिए बस्तर लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं. वहीं इस सीट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी दावेदारी ठोकी है. अब इन सबके बीच दोनों नेताओं ने मुलाकात की है. मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि, दोनों में से कोई एक नेता मान गया है. हालांकि दोनों ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है. बता दें कि कवासी लखमा पीसीसी चीफ से मिलने उनके घर पहुंचे थे. सियासी गिलयारों में चर्चा है कि कवासी लखमा चाहते हैं कि बस्तर से उनके बेटे को सांसद का टिकट मिल जाए. इसके लिए लखमा ने एआईसीसी में अपने बेटे की दावेदारी पेश की है और इसी सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में जीतकर आए दीपक बैज ने भी अपनी दावेदारी पेश की है. जानकारी के अनुसार, कांग्रेस को दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के रणनीतियों पर चर्चा की है. मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा, इस बार हम सब और अधिक मजबूत से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और न्याय की गारंटी को जन-जन तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे.

कांग्रेस की खुद अपनी कोई गारंटी नहीं रही, वो जनता को गारंटी दे रही हैं

रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों के लिए पांच न्याय गारंटी दी हैं इसे महज चुनावी सब्जबाग दिखाना करार देते हुए भाजपा विधायक द्वय मोतीलाल साहू एवं पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की देश में अपनी कोई साख नहीं बची हैं अब वो देश की जनता को 5 न्याय की गारंटी दे रही हैं ये महज़ चुनावी सब्जबाग दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। झूठ परोसना कांग्रेस की फितरत में ही हैं। देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती हैं और वो है मोदी की गारंटी। इनकी गारंटी के आगे सभी की गारंटी कहीं भी नहीं टिकती हैं। अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रही कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से इस तरह के झूठे वादे नहीं करना चाहिए? 50 वर्षों तक देश में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार की सेवा, सत्कार में लगी रही। जनता के दुःख - तकलीफों से इनका कोई सरोकार नहीं रहा? सत्ता सुख भोगते - भोगते कांग्रेसी शायद यह भूल गए कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन हैं कभी लोकसभा में चार सौ सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज दहाई के आंकड़े तक सिमट कर रह गई है। देश ने दस साल यूपीए सरकार के शासन को भी देखा है जब सारे फैसले दस जनपथ से पूछकर लिए जाते थे।

भाजपा विधायक द्वय ने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों में इनके सारे बड़े नेता लिप्त रहे। आखिर किस मुंह से कांग्रेस देश की जनता के पास वोट मांगने जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास न कोई नीति है और न ही विकास कार्य करने की नियत वर्ष 2014 का वो स्वर्णिम काल आया जब एक गरीब मां का बेटा नरेन्द्र मोदी भारत देश का प्रधान सेवक बना

और देश आज सफलता की ऊंचाईयों को छू रहा हैं यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही नितियों का ही असर है कि आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे और भारत देश विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि देश की जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को तलाश रही हैं और जब मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर पायी तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेकर इंडी (घमंडिया) गठबंधन बना लिया।

सारे विरोधी एक हो गए और इनके गठबंधन में ही कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है बहुत से राज्यों में तो कांग्रेस ने अपने आधे ही उम्मीदवारों की घोषणा की हैं। दरअसल कांग्रेस का अपने ही सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही हैं।

आलाकमान के दबाव में चुनाव लड़ रहे भूपेश

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सीएम, मंत्री तो क्या एक और दो नंबर वाले भी

आ जाएंगे तो कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे वाले बयान पर कहा कि भूपेश बघेल आज चारों ओर से घिरे हुए हैं। भूपेश बघेल आला कमान के दबाव में चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में भ्रष्टाचार का इनोवेशन की है।

वहीं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन कोरबा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को कांग्रेस द्वारा बाहरी बताए जाने पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ज्योत्सना महंत क्या कोरबा लोकसभा से हैं? वे भी जांजगीर से हैं ऐसे में तो वे भी बाहरी हैं? ज्योत्सना महंत डीएमएफ के भ्रष्टाचार में शामिल हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए बस्तर में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्तर से भाजपा ने महेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है।

प्रथम चरण में 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की 11 में से एकमात्र बस्तर सीट पर चुनाव होने हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रथम चरण में चुनाव तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार के चुनाव में पहली बार होगा, जब प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से होंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

कांग्रेस की पांच गारंटी के आगे मोदी की गारंटी फेल

रायपुर। भाजपा विधायकद्वय मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता को भाजपा को 10 साल सरकार चलाने का अवसर देने का आज पछतावा हो रहा है। इन 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जनता से सिर्फ वादाखिलाफी किया है। जनता बदलाव की मूड बना चुकी है। भाजपा नेताओं को केंद्र में परिवर्तन की लहर दिख रही है इसे घबराये भाजपा के नेता मोदी की नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस के गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने ही देश का निर्माण किया है देश को संवारा है और कांग्रेस ही देश चला सकती है. यह जनता ने भी स्वीकार कर लिया है मोदी के 10 साल के कार्यकाल हर वर्ग इनके कुनीतियों से पीड़ित है। 10 साल से जनता सिर्फ ड्रामा बाजी जुमला बाजी और मन की बात सुन रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की पांच गारंटी जनता के सामने आने के बाद मोदी की गारंटी का ढिंढोरा और ढोल पीटने वाले भाजपा नेताओं को पसीना आने लगा है।

भाजपा की सरकार बनने पर राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त -कांग्रेस

रायपुर। भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है। मासूम बच्चियों के साथ घृणित दुराचार की घटनायें बढ़ गयी। रोज समाचारों में प्रदेश भर में तीन से चार मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरे सामने आ रही। तीन माह में प्रदेश में 36 से अधिक हत्याओं की घटना हो गयी है। राजधानी रायपुर में तीन गोलीकांड हो गया, लूट, चाकूबाजी, चैन स्नेचिंग तो रायपुर की पहचान बन गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा राज के तीन महिने में ही छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। भाजपा राज में अपराधी बेलगाम हो गये। प्रदेश में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। दुर्ग में 16 वर्ष की एक मासूम बच्ची के गले में ब्लेड मार कर हत्या की कोशिश किया गया। दो महिने में राजधानी में सरेआम गोलीबारी की दो घटनायें हो गयी। राजिम में एक 10 वर्षीय नाबालिक बच्ची के साथ इसी हफ्ते बालोद जिले में 2 वर्षीय बच्ची के साथ, अंबिकापुर जिले में नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटती है।

शहर के इन क्षेत्रों में आज शाम पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित

रायपुर। राजधानी में बिजली विभाग की ओर से बुधवार सुबह 33 केवी सप्लाई लाईन बन्द कर मेन्टेन्स किया गया. इस वजह से शहर की 23 टंकीयों में भरपूर मात्रा में पेयजल नहीं भर पाया है. इन टंकीयों से जुड़े क्षेत्रों में आज शाम पानी सप्लाई आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी. रायपुर नगर निगम के फिल्टर प्लांट विभाग के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंद्र ने बताया कि आज सुबह मेन्टेन्स के चलते बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई साढ़े तीन घण्टे तक बन्द रखा था. इस वजह से शहर के चंगोराभाठा, डीडी नगर, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, रामनगर, गोगांव, जरवाय, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, सड्डू, दलदल सिवनी, कचना, आमसिवनी, राजेंद्रनगर, श्यामनगर, खमतराई, डंगनिया, गंज और गुढ़ियारी की पानी टंकीयों में भरपूर क्षमता के साथ जलभराव नहीं हो पाया. इसके कारण इन क्षेत्रों में आज शाम पेयजल आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी. वहीं गुरुवार सुबह पेयजल सप्लाई सुचारू हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ के इन 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी

रायपुर। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यहां पर बारिश के साथ अंधड़ चलने का अनुमान जताया गया है। जिसमें कहा गया है कि अगले 03 घंटों में येलो अलर्ट दर्शाये गए जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। बस्तर संभाग के कुछ जिलों को छोड़ सभी संभागों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इधर बेमेतरा जिले में भी तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। किसानों के खरबूजा और केला की फसल बर्बाद हो गई है। बारिश से तापमान में काफी गिरावट आई है। इधर सरगुजा संभाग के वाड्रफनगर से खबर है कि यहां पर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी तूफान के साथ यहां जमकर ओले गिरे हैं। वाड्रफनगर के कुछ हिस्सों में काफी ओलावृष्टि हुई है। जिसकी वजह से किसानों की गेंहू, सरसों और सब्जियों के खेती को बहुत नुकसान हुआ है।

कांग्रेस नेता ने भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग की,

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की टिकट से पूर्व मुख्यमंत्री और कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव से प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ रोज नए नए मामले आ रहे है। कभी बीजेपी तो कभी उनकी ही पार्टी के नेता आरोप या खुलासा कर रहे है। इस बीच आज एक कांग्रेस नेता ने तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से से की है। क्या है पूरा मामला? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। लेकिन राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर रोज नए-नए मामले आ रहे हैं। पहले भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जिहादी झंडा लिए कार्टून में दिखाए। इसके बाद राजनांदगांव में कांग्रेस के पदाधिकारी सुरेंद्र दाऊ ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई। तो एक बार फिर से आज सुरेंद्र दाऊ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर राजनांदगांव लोकसभा से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग करते हुए स्थानीय को टिकट देने की बात कही है। इतना ही नहीं उन्होंने भूपेश बघेल पर भाजपा का साथ देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा की 2018 और 2023 के चुनाव में राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशियों को उतारा गया।

होली से पहले दिल्ली में लगा किसान का मेला

छत्तीसगढ़ के शुद्ध और जैविक उत्पादों की डिमांड, जमकर हो रही खरीदारी

नई दिल्ली/रायपुर। होली से पहले दिल्ली में किसानों का मेला लगा है, जहां छत्तीसगढ़ से शुद्ध और जैविक उत्पाद लेकर महिला किसान शामिल हुई हैं। जिसे खरीदने के लिए, लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की तरफ से दिल्ली के हौज़ खास स्थित एनसीडीसी कैंपस में किसान उत्पादक संगठन (स्वक्ष) का मेला लगा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले में 18 राज्यों के 40 किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए हैं। इस मेले में किसान

संगठनों की शानदार प्रदर्शनी लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सत्य साईं महिला बहुद्देशीय सहकारी मर्यादित द्वारा अपने क्षेत्र में तैयार उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में दिल्ली के अलावा दूर-दूर से आए लोग शुद्ध और जैविक उत्पाद खरीद रहे हैं। यहां लोग मिलेट्स यानी मोटे अनाज और उससे बने अलग-अलग उत्पादों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध और बेहतर क्वालिटी के शहद, मसाला, आचार, साबुन आदि जैसे कई उत्पाद उपलब्ध हैं। स्टाल में मोटे अनाज व सोयाबीन से बना मल्टीग्रेन आटा उपलब्ध है, जो कि वेटलॉस, डाइजेशन, इम्युनिटी के लिए काफी कारगर है। इसके अलावा अलग-अलग फ्रेगरेंस के लीपबाम, सोप, फूट क्रीम लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। खासकर वनीला, ग्रेप्स व ऑलिव ऑइल से बने लीप बाम की खास डिमांड है। वहीं, बाजार के मुकाबले इनकी कीमत भी काफी कम है।

सत्य साईं महिला बहुद्देशीय सहकारी मर्यादित से जुड़ी गिरिजा बंजारी ने बताया कि उनके संगठन से 300 से ज्यादा महिला किसान जुड़े हैं। ये महिलाएं कई तरह के जैविक उत्पादों को तैयार करती हैं। जिसे देश के अलग-अलग हिस्सों में बेचा जाता है। उन्होंने बताया एनसीडीसी के अधिकारियों को भी स्टाल के उत्पाद काफी पसंद आए, उन्होंने भी खरीदारी की है।

रामलला दर्शन योजना : हाईकोर्ट ने योजना पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज

बिलासपुर. रामलला के दर्शन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता ने इसे धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल एजी यशवंत सिंह ठाकुर ने सरकार की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा कि रामलला दर्शन प्रदेश के सभी वर्गों के लिए है. यह धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं है. रामलला के दर्शन के लिए सभी धर्म के लोग जाते हैं. हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश की गई इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

दरअसल, राज्य शासन की ओर से छत्तीसगढ़वासियों के लिए रामलला के दर्शन की योजना शुरू की गई है. जिसमें लोगों को अयोध्याधाम लेकर रामलला के दर्शन कराकर वापस लाया जाता है. बिलासपुर जिले के देवरीखुर्द निवासी याचिकाकर्ता लखन सुबोध ने इसे संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए इस योजना को बंद करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. रामलला दर्शन योजना संविधान में निहित बातों और शर्तों के विपरीत है. उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर तर्क देते हुए योजना को बंद करने के लिए राज्य शासन को आदेशित करने का आग्रह किया था.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.